न्यू देहली पोस्ट

■ वर्ष 13 ■ अंक 11 रविवार (साप्ताहिक) 23 मार्च 2025 ■ पृष्ठ 16 ■ मूल्य 5 रुपये

चैम्पियंस ट्रॉफी में जीत के बाद नोटों की बरसात

अंदर विशेष

दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित
पृष्ठ 3 पर

मुफ्त योजनाओं पर इनफ्रोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति ने किया हमला
पृष्ठ 5 पर

मोहन सरकार के बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं
पृष्ठ 7 पर

क्या संभल बनेगा सियासत का नया केंद्र?
पृष्ठ 9 पर

महाराष्ट्र में सरकार बदलती गई नहीं रुकी किसानों की आत्महत्या
पृष्ठ 11 पर

क्या नेपाल में फिर लौटेगी राजशाही?
पृष्ठ 15 पर

योगी सरकार का
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे घोटला

न्यू देहली पोस्ट डेस्क

कागज यानि दस्तावेज...कागज पर कलम से जब शब्दों को उकेरा जाता है तो फिर कागज,कागज नहीं रहता। यह दस्तावेज बन जाता है। कहते है कि सरकारी दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलते। न्यू देहली पोस्ट ने "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे" के सरकारी दस्तावेजों की फाइल खोली है।अब यही दस्तावेज गवाही देंगे जो साक्षी हैं उत्तरप्रदेश के एक घोटाले के। इस घोटाले ने कर दिया है मिस्टर क्लीन को क्लीन बोल्ड। कल तक सीएम योगी खुद को साफ़ सुथरी इमेज वाले नेता कहते थे लेकिन उनके राज काज में जिस तरह से ख़ास ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है उससे सूबे के राजकोष को करीब 540 करोड़ की छति हुई है। सीएम योगी एक मठ के महंत है और मंहत अवैधनाथ के शिष्य भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी एक प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सनातन की भाषा ही समझते हैं। सनातन प्रचार करते हैं और सनातन को लेकर ही जीते हैं। ....

''अक्षरं परमं ब्रह्म सांख्यम सनातनम्। '' ."पूर्वांचल एक्सप्रेसवे घोटला" में आपको दो रकम दिखाई गयीं हैं। अक्षर करोड़ का हैऔर संख्या 104.01 और 540 है। सारा खेल इन दो अक्षरों और संख्याओं के बीच में ही है। खैर अब मुद्दे पर आते हैं। "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम समय से पहले समाप्त होने पर 338.90 करोड़ दिया जाना था। लेकिन दिया गया 431.85 यानी कि 92.95 करोड़ रुपए अधिक। इस रकम में 12% जीएसटी 11.15 करोड़ जोड़ दें तो यह रकम 104.01 करोड़ हो जाती है। कैग रिपोर्ट में इन दोनों रकमों पर ही सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे" मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी प्रगति पर उन्होंने खुद

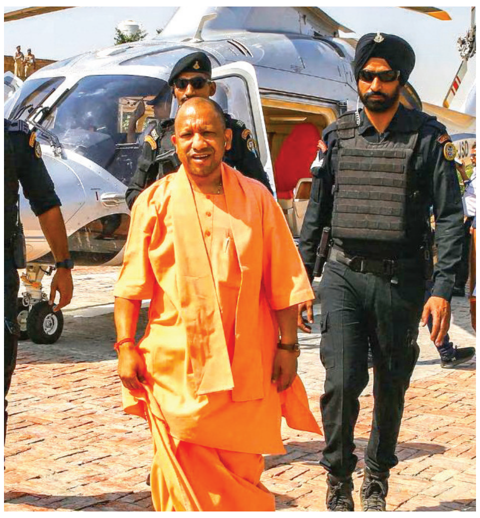

ही नज़र रखी और खूब प्रचार भी किया। उत्तरप्रदेश के प्रिंसिपल अकाउंट जनरल की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वांचल निर्माण एक्सप्रेस वे निर्माण के क्रम में नियमों का उल्लंघन करते हुए अनुचित तरीके से 104.01 करोड रुपए के अर्ली कपम्प्लीशन बोनस यानी शीघ्र समापन बोनस की बंदर बांट की गयी।

आगे बढे इससे पहले यह जानना जरुरी है कि अर्ली कंप्लीशन बोनस यानी शीघ्र समापन बोनस कब कैसे और क्यों दिया जाता है?जैसा कि नाम से ही तय है कि जब सरकार या किसी एजेंसी द्वारा आबंटित काम को कोई ठेकेदार या कोई कंपनी तय समय से पहले पूरा कर लेती है तब उस कंपनी या ठेकेदार को शीघ्र समापन बोनस दिया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने इस संबध में एक गाइडलाइन बनाई है जिसमें बोनस की रकम कब कैसे और कितनी मिलेगी तय किया गया है।

शेष १ पर

स्टारलिंक की भारत में दस्तक
अंबानी और मित्तल ने किया मस्क के सामने सरेंडर

इमरान खान

शार्क जब शिकार पर निकलती है तो छोटी मछलियों को अपना भोजन बना लेती है,लेकिन शार्क खुद नहीं जानती है कि एक बड़ी शार्क उसको भी अपना निवाला बना सकती है। इंडिया के शार्क कहे जाने वाले मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल इनको भी कोई बड़ी शार्क अपना भोजन बना सकती है.इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसा ही भारत में देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने स्टारलिंक को हरी झंडी दे दी है .. और हरी झंडी मिलने के बाद ही दोनों ने स्टारलिंक के सामने सरेंडर कर दिया है।

इंटरनेट की दुनिया में बड़ा उलटफेर हो गया। कल्पना से परे। पहले विरोध लेकिन अब साझेदारी! जिस स्टारलिंक का एयरटेल और जिओ विरोध कर रहे थे अब यही कंपनियां इसे भारत में बेचने जा रही हैं।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते मंगलवार को एयरटेल ने बताया कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ उनका करार हो गया है। लगे हाथ मुकेश अंबानी की कंपनी जिओ ने भी घोषणा कर बताया कि उनका भी स्टारलिंक के साथ करार हो गया है। यानी अब स्टारलिंक भारत में एयरटेल और जिओ के साथ मिलकर काम करेगा।

शेष १ पर

पाकिस्तान का आरोप : रॉ की पैदाइश है बलूच लिबरेशन आर्मी?

न्यू देहली पोस्ट

इस महीने की ग्यारह तारीख को बलूच लिबरेशन आर्मी ने दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस के 500 यात्रियों को बंधक बना लिया जिसकी वजह से बलूच लिबरेशन आर्मी अचानक सोशल मीडिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक हॉट सब्जेक्ट बन गयी।

हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि सेना ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन 300 से अधिक यात्रियों को बचा लिया है और इस ऑपरेशन में 33 आतंकवादी को मार गिराया है। लेकिन अफसोस यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के इस हमले में 21 बंधक यात्री भी मारे गए। पाकिस्तान के पत्रकार,पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और

पाकिस्तान सरकार बलूच लिबरेशन आर्मी को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की पैदाइस मानती है। लेकिन भारत हमेशा से ऐसे आरोपों का खंडन करता आया है। सच तो यही है कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और किसी भी हिंसक गतिविधि का कभी भी समर्थन नहीं करता है।

बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने बलूच लिबरेशन आर्मी की पैदाइस और उसके आतंकी हमलों को लेकर एक लेख लिखा है और उस लेख में इशारा किया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी भारत की खुफिया एजेंसी, रॉ की पैदाइस है। आइए जानते हैं एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसे हामिद मीर ने भारत प्रयोजित बताने की कोशिश की और अपने एक ब्लॉग में बलूच लिबरेशन आर्मी को रॉ से जोड़ा है।

हामिद मीर ने क्या लिखा ?

हामिद मीर अपने ब्लॉग में कुछ घटनाओं की जिक्र करते हैं। घटना 1998 की है बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर नई दिल्ली ले जाने की कोशिश की। शेष १ पर

योगी सरकार का...

बोनस की यह राशि 0.03% हो सकती है लेकिन शर्त यही है कि काम को पूरा कर लिया गया हो। और इस काम को पूरा करने का सर्टिफिकेट विभागीय इंजीनियर ने जारी कर दिया हो। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस घोटाले में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम पूरा होने से पहले ही ठेकेदार कंपनियों को शीघ्र समापन बोनस दे दिया गया। घोटाले का खेल यहीं से आरंभ हुआ। .इतना ही नहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने जो बोनस की राशि तय की है उसे भी बड़ा कर 0.04% कर दिया गया। जिसके कारण सरकार 540 करोड रुपए की राजकोष की क्षति हुई। अब यह राशि क्यों बढ़ाई गई और किसके आदेश पर बढ़ाई गई यह भी जांच के घेरे में है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस घोटाले में आगे बड़ने से पहले जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की खास बातें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट कॉस्ट 22,494.66 करोड़ रुपए रखा गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर बताई जाती है। भारतीय वायुसेना के आपातकालीन लैंडिंग के लिए 3.20 किमी लंबी और 34 मीटर चौड़ी सीमेंट और कंक्रीट की सड़क भी बनाई गई ताकि आपात स्थिति में यहाँ हवाई जहाज को उतारा जा सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आठ पेट्रोल पंप और चार सीएनजी स्टेशन हैं भी बनाने का दावा किया गया है और इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 4.50 लाख पेड़ लगाए जाने की बात भी कही जा रही है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी का निर्णाण किया गया है। यह अभी 6-लेन का (प्रत्येक दिशा में 3-लेन) एक्सप्रेसवे है जिसे आठ लेन तक बढाये जा सकने लायक बनाया गया है। 2021 तक यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना गया । एक्सप्रेसवे पूर्व में गाजीपुर शहर से राज्य की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज (चांद सराय) गाँव को (आजमगढ़ और अयोध्या के माध्यम) से जोड़ेता है। इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 22,494 करोड़ की लागत जिसमें भूमि अधिग्रहण का मूल्य भी शामिल है से विकसित किया गया है।

इस एक्सप्रेसवे के बारे में कहा गया है कि यह लखनऊ से गाजीपुर के बीच 9 जिलों से होकर गुजरेगा जिनमें प्रमुख हैं- लखनऊ से शुरु होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में समाप्त हो जाएगा।एक्सप्रेसवे को वाराणसी - गोरखपुर राजमार्ग के साथ एक अलग लिंक सड़क के माध्यम से जोड़ा जाना है। इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में यूपीडा के द्वारा इसके भूमि अधिग्रहण के समाप्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किये जाने के बाद शुरु हुआ और 16 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन करने के बाद जनता को समर्पित हुआ। बाद में इस एक्सप्रेस वे को एक लिंकवे द्वारा आजमगढ़ में सलारपुर गांव के पास से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे द्वारा गोरखपुर के जैतपुर गाँव से और आजमगढ़-वाराणसी राजमार्ग से भी जोड़ा जाना था। कहा गया कि इससे दिल्ली से गाजीपुर तक गाजीपुर तक की यात्रा 10 घंटे में सड़क मार्ग से पूरी की जा सकेगी। समाजवादी पार्टी के अनुसार इस परियोजना का संकल्पन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था जिसका वो श्रेय लेना चाहते थे लेकिन शिलान्यास, संपूर्ण निर्माण और उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होने की वजह से यह दोनों दलों के बीच बहस और श्रेय लेने का एक चुनावी मुद्दा भी बना।

इस एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत मुख्य कैरिज-वे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास निर्मित किए गए हैं। सुल्तानपुर में इस मार्ग के एक हिस्से को वायुसेना के विमानों के उतरने लायक 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है। इसके उद्घाटन के लिये नरेंद्र मोदी सेना के हर्क्युलीज़ सी130जे विमान से इसी हवाई पट्टी पर उतरे जो कि इसकी मजबूती और इतने बडे विमानों को संभाल सकने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। इसके भूमिअधिग्रहण और निर्माण की कुल कीमत लगभग 21500 करोड़ रूपये हैं जिसमें निर्माण पर 11000 करोड़ खर्च हुए हैं। तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खास बातें।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आप भी जाएं और देखें कि क्या सच में सरकार ने आपके टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल किया है या नहीं ?आइए एक नजर डालते हैं वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.- III के द्वारा दिनांक 20/09/2022 को लिखे गए पत्र पर। पत्र संख्या म०ले० (ऑडिट-II)/एएमजी-II/ए.आई.आर -1/2022-23/ एक प्रार्थना पत्र है जिसमे कहा गया है कि -महोदय,उपर्युक्त कार्यालय की लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियां आपको प्रेषित की जा रही है। लेखापरीक्षा द्वारा उठायीं गर्मी आपतियों के उत्तर प्राप्त करके उच्चाधिकारी की टिप्पणी सहित इस कार्यालय को एक मांह के अंदर प्रेषित का कष्ट करे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गोपनीयता सुनिश्चित करे।

कैग रिपोर्ट भाग-11 की संदर्भ संख्याः ओबीएस -337151 पैरा एक में लिखा है सकिरकारी गाइडलाइन को ताक पर रखकर 104.10 करोड़ रुपए बोनस का भुगतान कर दिया गया। कैग रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यूपीडा यानी " उत्तरप्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ईपीसी समझौते में निर्धारित बोनस निर्धारण के प्रचलित मानक दरों को अपनाने में विफल रहा है। इस मामले में उच्च दरों से बोनस की अनुमति दी गयी, जिसके कारण सरकार को 104.10 करोड़ का नुकसान हुआ। कैग की इसी रिपोर्ट के रेफेन्स नंबर ओबीएस -331054 और पारा -2 में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कंपनियों को आबंटित टोल प्लाजा अलॉटमेंट में भी धांधली की गयी है।

सरकार को 35.59 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी कम चुकाई गयी जिससे सरकार को 35.59 करोड़ रुपए का नुकसान अलग से हुआ है। अब इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन लोग है इसकी जानकारी तो सीएम योगी ही दे सकते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के दम पर चमचमाती सड़क के नाम पर चल रही वोट की राजनीति जनता के पैसों पर कितनी चमकती है इसकी बानगी के तौर पर आप यूपी की योगी सरकार को देख सकते हैं।

पाकिस्तान का आरोप...

हामिद कहते हैं कैप्टन उजैर खान की सूझबूझ और पाकिस्तानी अधिकारियों ने अलगाववादियों की साजिश को नाकाम कर दिया था। पाकिस्तानी जहाज के कैप्टन ने जहाज को भारत के भुज में लैंड करने की परमिशन के लिए कहा और अंधेरे का फायदा उठा कर जहाज को पाकिस्तान के हैदराबाद में उतार दिया। जहाज लैंड होने के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी के अपहरणकर्ताओं ने भारत के मीडिया चैनल जी न्यूज़ को एक इंटरव्यू देने की मांग की। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बलूच लिबरेशन आर्मी से कहा कि जल्दी ही इंटरव्यू की टीम भुज पहुंच जाएगी बलूच लिबरेशन आर्मी को अब तक यही मालूम था कि वह इंडिया-गुजरात के भुज में है।

जब कई घंटो तक जी न्यूज़ की टीम एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची तब बलूच लिबरेशन आर्मी के आतंकियों को शक हुआ। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने एक बार फिर बहाना बनाया और आतंकियों को बताया जी न्यूज़ की टीम भुज में नहीं है और दिल्ली से उसे बुलाया गया है, इस लिए समय लगेगा। बलूच लिबरेशन आर्मी एक बार फिर आईएसआई के झांसे में आ गई...पाकिस्तान पुलिस के लिए इतना समय काफी था। एसएसपी अख्तर गोरचानी और एएसपी उस्मान अनवर ने इस पूरे ऑपरेशन में हिंदी में ही बातचीत की और खुद को भारतीय पुलिस की तरह पेश किया। इन अधिकारियों ने एक बार फिर बहाना बनाया और आतंकियों से जहाज के यात्रियों के लिए खाने के इंतजाम की परमिशन ली। पाकिस्तान का एक और दस्ता अस्त्र-शस्त्र के साथ जहाज में खाना लेकर पहुंच चुका था। और फिल्मी अंदाज में इस दस्ते ने आतंकियों को अपने कब्जे में कर लिया। बाद में 2015 में इन अपहरणकर्ताओं को फांसी दे दी गई। हामिद मीर अपने ब्लॉग में आगे कहते हैं कि 2025 के हालात 1998 के जैसे नहीं हैं। अब हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस बार क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन का अपहरण करके पाकिस्तानी सुरक्षा को गंभीर चुनौती दे दी है। इस पूरी कहानी में हामिद मीर ने बलूच लिबरेशन आर्मी को भारत की रॉ प्रायोजित बताने की कोशिश की है।

आइये जानते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी के इतिहास पर जिसने पाकिस्तान की चूलें हिला दीं हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहां सबसे कम आबादी है। बलोच पहाड़ी और रेगिस्तानी के कबीलों में रहते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की स्थापना 2000 के दशक में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुई थी। बता दें कि बीएलए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अक्सर गुरिल्ला युद्ध आजमाती है। बलोच लिबरेशन आर्मी खास कर टारगेट हत्याओं के लिए जानी जाती है। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन पाकिस्तान में बलूचों के शोषण ,उत्पीड़न और हिस्सेदारी के कारण सन दो हजार के पहले दशक में हुआ। धीरे-धीरे इस संगठन ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना आरंभ कर दिया और कालांतर में स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगा।

कौन हैं बलूच ?

बलोच, बलौच या बलूच दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत में बसने वाली एक जाति है। यह बलोच भाषा बोलते हैं, जो ईरानी भाषा परिवार की एक सदस्य है जो स्वयं वैदिक संस्कृत की बड़ी क़रीबी भाषा मानी जाती है। एक ब्राहुई नामक समुदाय भी बलोच माना जाता है, हालांकि यह एक द्रविड़ भाषा परिवार की ब्राहुई नाम की भाषा बोलते है। यह वही भाषा है जिसके प्रचीन शिलालेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए। प्रोफेसर डॉ. अब्दुर रज्जाक साबिर द्वारा लिखित पहला अध्याय बलूचिस्तान के इतिहास का संक्षिप्त सारांश देता है, जिसे मानव सभ्यता के शुरुआती उद्गमों में से एक माना जाता है क्योंकि बलूचिस्तान में पाया गया मेहरगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल लगभग 7,000 ईसा पूर्व का माना जाता है।डॉ. साबिर कहते हैं कि ब्राहुई भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि द्रविड़ भाषाओं की लिपियाँ, जिनमें ब्राहुई की लिपि भी शामिल है, अशोक के स्तंभों पर लिखे शिलालेखों से ली गई हैं, जिन्होंने 268 ईसा पूर्व और 232 ईसा पूर्व के बीच भारत पर शासन किया था।

कौन है बलूच लिबरेशन आर्मी का मास्टरमांइड?

बीएलए का नेतृत्व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया है, जिसमें असलम बलूच (असलम अचू) 2018 में अपनी कथित मृत्यु तक सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक था। अन्य प्रमुख व्यक्तियों में बशीर ज़ेब बलूच और डॉ. अल्लाह नज़र बलूच शामिल हैं।

लिबरेशन आर्मी का सशस्त्र विद्रोह कब कैसे आरंभ हुआ ?

बीएलए ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी अधिकारियों और बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के खिलाफ कई हमले किए हैं, विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपेक के तहत चीनी हितों को निशाना बनाकर।

पाकिस्तानी आर्मी पर कब कैसे निशाना ?

बलूच लिबरेशन आर्मी ने 2004 में बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइनों पर बमबारी की। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 2018 में कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 2019 में ग्वादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया। बलूच लिबरेशन आर्मी 2022 में कराची विश्वविद्यालय में आत्मघाती हमला, जिसमें चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। और बलूच लिबरेशन आर्मी तारीख ग्यारह को दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया और 500 लोगों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर बीएलए को एक आतंकवादी संगठन मानता है। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने भी इसे आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन बीएलए को एक उत्पीड़ित संगठन मानता है।

स्टारलिंक की भारत...

लेकिन ये डील बिरला समूह की कम्पनी वोडाफोन और आइडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में पहले से ही सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करना चाहती थी, लेकिन जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध कर रही थी। लेकिन अब वही जिओ और एयरटेल स्टारलिंक के साथ डील करने को तैयार हैं। आखिर जियो -एयरटेल जैसी कंपनियों ने क्यों सरेंडर किया? यह सरकार की कोई बिजनेस पॉलिसी है ? या किसी को अमेरिका को खुश करने की रणनीति? यह बड़ा सवाल है। इसके पीछे दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं— पहली, सरकार का रुख और दूसरी, बिजनेस ग्रोथ! सरकार ने साफ कर दिया कि स्पेस-आधारित इंटरनेट को आगे बढ़ाया जाएगा और नियमों का पालन करके स्टारलिंक को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा, 5जी और ब्रॉडबैंड विस्तार की दौड़ में जियो और एयरटेल को एहसास हुआ कि स्टारलिंक उनके लिए खतरा नहीं, बल्कि एक नया बिजनेस मॉडल हो सकता है। इसलिए, अब दोनों कंपनियां स्टारलिंक के साथ काम करने के लिए राजी हो गई। समझना ये है कि आखिर इंडियन ओशन और पेसिफिक ओशन की बड़ी शार्क एक ही नाव में कैसे सवार हो गई ? यानी पहले जो दुश्मन थे, अब वही साझेदार बन गए! सवाल ये भी उठता है कि क्या ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए कितना फायदेमंद होगा?भारत के बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं।

ग्रामीण भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट

स्टारलिंक सैटेलाइट-बेस्ड इंटरनेट सेवा देती है, जिससे दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट की पहुंच आसान हो जाएगी। भारत में अभी भी लाखों गांव ऐसे हैं, जहां ब्रॉडबैंड या 5जी नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। जियो और एयरटेल की साझेदारी से यह गैप तेजी से भरा जा सकता है।

5जी और ब्रॉडबैंड विस्तार को बूस्ट मिलेगा

जिओ और एयरटेल पहले ही 5जी विस्तार पर काम कर रहे हैं। स्टारलिंक के आने से नेटवर्क का कवरेज और मजबूत होगा, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी 5 जी और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर हो सकेगी।

टेलीकॉम कंपनियों के लिए नया बिजनेस मॉडल

जिओ और एयरटेल के पास पहले से ही करोड़ों ग्राहक हैं। अगर वे अपने मौजूदा नेटवर्क के साथ स्टारलिंक की सेवाओं को भी जोड़ते हैं, तो यह उनके लिए एक नए रेवेन्यू मॉडल का जरिया बन सकता है। खासकर, प्रीमियम ग्राहकों और बिजनेस सेक्टर में इसकी मांग ज्यादा होगी। अभी हमने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे आपको फायदा होगा। लेकिन अब हम आपको बताते है कि दुनिया की बड़ी शार्कों के एकजुट होने से भारत के बाजार को क्या-क्या नुकसान होगा।

डेटा सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं

स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं सस्ती नहीं हैं। अभी इसकी बेसिक सर्विस 99 डॉलर (8,000 के करीब) में मिलती है। अगर जिओ और एयरटेल इस सेवा को रिसेल करते हैं, तो इसकी कीमत और बढ़ सकती है। इससे आम ग्राहकों के लिए यह सेवा किफायती नहीं रह सकती।

फाइबर ब्रॉडबैंड बिजनेस को नुकसान

भारत में जिओ फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अगर स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लोकप्रिय हो गई, तो यह ब्रॉडबैंड बिजनेस के लिए चुनौती बन सकती है। खासतौर पर ऐसे ग्राहक, जो बिना तारों की झंझट के सीधे हाई-स्पीड इंटरनेट चाहते हैं।

भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की आत्मनिर्भरता पर असर

अब तक भारतीय टेलीकॉम सेक्टर देशी कंपनियों के नियंत्रण में था। लेकिन स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनी के भारत में प्रवेश से डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बाहरी नियंत्रण बढ़ सकता है। इससे साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे भी खड़े हो सकते हैं। जिओ के मुकेश अंबानी और एयरटेल के सुनील मित्तल जैसे मगरमच्छ या शार्क.जैसा आप ठीक समझे क्यों एक वोट में सवार हो गए ये एक गहरा रहस्य है। इतना तो स्पष्ट है दुनिया की बिजनेस के दिग्गज टाइकून एक वोट में किसी घाटे के लिए तो सवार नहीं होंगे। इंटरनेट के मार्केट में यूजर्स को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। ये वक्त ही तय करेगा।

न्यू देहली पोस्ट
23 मार्च 2025
संपादकीय कार्यालय : मुद्रक व प्रकाशक आशीष कुमार द्वारा विभा पब्लिकेशन डी-160 बी, सेक्टर-7, नोएडा से मुद्रित एवं 262ए, सेक्टर-4, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित। RNI NO. UPHIN/2013/49239
संपादक : आशीष कुमार, **प्रसार प्रबंधक** : दशरथ सिंह
Postal registration Number: UP/GBD-181/2013-15, **हमसे संपर्क करें** : postnewdelhi@gmail.com

न्यू देहली पोस्ट

संपादकीय

यहूदी समुदाय के निशाने पर ट्रंप सरकार

अमेरिका में ट्रंप सरकार सकते में है। ट्रंप सरकार के खिलाफ यहूदी समुदाय का गुस्सा उफान पर है। ट्रंप टावर के बाहर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लग गया। प्रदर्शन इतना उग्र रहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप टावर के अंदर घुसने की भी कोशिश की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से यहूदी और फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही, कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र महमूद खलील की गिरफ्तारी के विरोध में भी यह आंदोलन हुआ। गौरतलब है कि खलील को हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने उनके ग्रीन कार्ड को भी रद्द कर दिया।

प्रदर्शन का आयोजन 'यहूदी वॉयस फॉर पीस' नामक संगठन द्वारा किया गया था। जैसे ही यह विरोध शुरू हुआ, बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने विशेष प्रकार की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिन पर "नॉट इन आवर नेम" और "इजरायल को हथियार देना बंद करो" जैसे नारे लिखे थे। इसके अलावा, उन्होंने "महमूद खलील को रिहा करो", "फिलिस्तीन को आजाद करो" और "पूरी दुनिया देख रही है" जैसे नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान स्थिति और अधिक गंभीर हो गई, जिसके चलते न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने करीब 98 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। महमूद खलील पर हुई कार्रवाई ने इस पूरे मामले को और अधिक तूल दे दिया। ट्रंप प्रशासन ने न केवल उन्हें गिरफ्तार किया बल्कि उनका ग्रीन कार्ड भी रद्द कर दिया।ट्रंप ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि अमेरिका "आतंकवाद समर्थकों" के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखता और ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि कई प्रदर्शनकारी वास्तव में छात्र नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलनकारी हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "हम इन आतंकवादी समर्थकों को खोजकर, पकड़कर और अमेरिका से बाहर निकाल फेंकेंगे ताकि वे फिर कभी वापस न आ सकें। अगर कोई निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवाद का समर्थन करता है, तो उनकी मौजूदगी हमारी राष्ट्रीय और विदेश नीति के खिलाफ है और उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इस नीति का पालन करना चाहिए।

बिहार चुनाव से पहले मंडल और कमंडल आमने -सामने

राजनीतिक डेस्क

बिहार चुनाव तो अक्टूबर -नवम्बर में होने हैं लेकिन बिहार की सियासी जमीन मंडल और कमंडल के सहारे बिहारी समाज को उद्वेलित किये हुए है। इस सियासी खेल का अंजाम क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता लेकिन इतना तो दिख रहा है कि इस बार बिहार की लड़ाई कल्पना से परे वाली होगी। एक तरफ महागठबंधन की अगुवाई करने वाली राजद आरक्षण की आग भी फिर से भड़का रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी संत और बाबाओं के जरिये बिहार की सियासी जमीन को धार्मिक रंग के जरिये राजद के आरक्षण वाले खेल को भोथरा करने को तैयार है। दोनों तरफ से केवल वोट की राजनीति की जा रही है। दोनों तरफ की अपनी भीड़ भी है। राजद का अपना जनाधार है और उसके अपने लोग भी हैं। उधर बीजेपी की अपनी जमीन है और उनके पास धर्म और आस्था के नाम पर बढ़ते वोट बैंक भी है। बिहार के कई इलाके आज बीजेपी के जाल में है तो यहाँ की अधिकतर जनता लालू यादव के खिलाफ बीजेपी के साथ खड़ी भी है। ऐसे में राजद और बीजेपी की यह लड़ाई कहाँ जाकर ख़त्म होगी यह कहना मुश्किल है लेकिन जिस तरह से बीजेपी बाबाओं के जरिये मंडल की राजनीति पर हमला करती दिख रही है उससे तो यही लगता है कि आगे की लड़ाई और भी रोचक होने वाली है।

बिहार का बड़ा सच तो यही है कि भले ही देश के कई राज्यों में भले ही जातीय राजनीति के साथ ही धार्मिक राजनीति भी कुलांचे मारती है और बीजेपी इसका बड़ा लाभ भी उठाती है। लेकिन बिहार में अब तक धर्म के नाम पर राजनीति होती नहीं देख गई। वहाँ जातीय खेल ही सर्वोपरि है और आज भी है। राजद के पास आज जो जातीय समीकरण है वही समीकरण पहले कांग्रेस के पास भी था। समय के साथ कांग्रेस की जातीय राजनीति राजद और कई अन्य दलों के साथ चली गई। कुछ जातियां जदयू के साथ गई तो कुछ जाति बीजेपी के साथ चली गई। आज सभी पार्टियों के साथ जातियां हैं लेकिन कांग्रेस जातिविहीन हो गई है। मजे की बात यह है कि नब्बे के दशक से ही जातीय राजनीति की परंपरा बिहार में चली आ रही है। पीएम रहते विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण पर बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। देश भर में इसके समर्थन और विरोध में सामाजिक विद्वेष चरम पर पहुंच गया। अगड़ों-पिछड़ों में खून-खराबा मंच गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पैदा हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए रथयात्रा निकाली। इसे राजनीतिक हलकों में कमंडल कहा गया। आज बीजेपी की राजनीति कमंडल के जरिये आगे चल रही है।

बिहार में लालू प्रसाद यादव और राजद फिर से आरक्षण समर्थक बन कर उभरे। सत्ता उनके हाथ में आ गई। तब वे पिछड़े समाज के मसीहा कहे गए। आरजेडी ने तब से चुनाव जीतने के अपने आजमाएं इस फार्मूले को अब तक नहीं छोड़ा है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में मंडल और कमंडल के बीच जंग की आरजेडी ने रूपरेखा बना ली है। आरजेडी ने फिर आरक्षण का राग छेड़ दिया है। इस बीच बीजेपी ने बिहार में बाबाओं को उतारना शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए बिहार को साधने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंच गए। सभी ने लोगों को साधा भी। भीड़ भी खूब जुटी। सबने अपने तरीके से बीजेपी के लिए जमीन तैयारी की। धीरेंद्र शास्त्री ने ''छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं'' के घोष वाक्य से भाजपा की जमीन तैयार की तो मोहन भगवत युवाओं को साधने में जुटे रहे। राजद नेता तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में परचम लहराने का कोई प्रयास छोड़ना नहीं चाहते। लालू यादव उनके राजनीतिक गुरु बने हुए हैं। जातीय गोलबंदी उनका पुराना खेल है। जातीय गोलबंदी से ही जुड़ा है आरक्षण का मामला। वर्ष 2015 के असेंबली चुनाव में आरक्षण का जिन्न जगा कर लालू ने कमाल कर दिया था। भाजपा चित्त हो गई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई थी। लगता है कि लालू ने बेटे तेजस्वी को फिर से आरक्षण का जिन्न जगाने का मंत्र दे दिया है। तेजस्वी ने पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने 65 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया।

तेजस्वी यादव धरने के वक्त भाजपा पर खूब बरसे। भाजपा को उन्होंने आरक्षण चोर तक कह दिया। लालू ने 2015 में कहा था कि भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष का यही नैरेटिव था। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान आरक्षण सीमा बढ़ा कर 65% की गई। मौजूदा एनडीए सरकार ने इसे लागू नहीं होने दिया। इससे पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का नुकसान हुआ। शिक्षक नियुक्ति में भी आरक्षण लागू नहीं होने से हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। जाहिर है इस बार बिहार में वह सब देखने को मिल सकता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं होगी ,बीजेपी को सत्ता चाहिए। नीतीश कुमार की राजनीति का क्या होगा यह अलग विषय हो सकता है। उधर राजद को भी इस बार सत्ता की भूख है। राजद किसी भी सूरत में बिहार में बीजेपी की सरकार देखना नहीं चाहती। हालांकि जनता क्या कुछ करती है और करेगी इसे कोई कैसे रोक सकेगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में मंडल और कमंडल की लड़ाई और तेज होगी। इस लड़ाई में बिहार को क्या मिलेगा यह सबसे अहम है।

दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित

न्यूज़ डेस्क

भारत की सरकार आखिर किस मुँह से दुनिया के सामने यह कहने से बाज नहीं आती कि भारत विश्वगुरु बनने के राह पर है और यह विकसित देशों की सूची में जल्द ही शामिल होगा। कहने को तो मोदी सरकार और भी बहुत सी बातें करते दिखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाना भी भारतीय लोगों को खूब भाता है लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के जरिये भारतीय लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है उसे भी दुनिया देख रही है। प्रेस की आजादी की बात हो या फिर मानवाधिकार के मामले में भारत की स्थिति का आकलन हो। या फिर हंगर में भारत की गरीबी की बात ही क्यों न हो। हर जगह हम नीचे ही तो खिसकते जा रहे हैं। धार्मिक उन्माद के मामले में आज भारत जहाँ पहुँच गया है उसकी चर्चा तो अब दूसरे कई देशों में भी हो रही है। अब वायु प्रदूषण के मामले में भी भारत की स्थिति काफी दयनीय बताई गई है।

स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी 'आईक्यूएयर' की मंगलवार को प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं और असम का बर्नीहाट इस सूची में सबसे ऊपर है। वहीं दिल्ली वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बनी हुई है, जबकि भारत 2024 में दुनिया का पांचवां सबसे प्रदूषित देश बन गया है। 2023 में इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर था। पड़ोसी देश पाकिस्तान के चार शहर और चीन का एक शहर दुनिया के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2024 में पीएम 2.5 सांद्रता में सात प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो 2023 में 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तुलना में औसतन 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं।दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, वार्षिक औसत पीएम 2.5 की सांद्रता 2023 में 102.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर 2024 में 108.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई।

दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत में असम का शहर बर्नीहाट, दिल्ली, पंजाब का मुल्लांपुर, हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लोनी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, राजस्थान में गंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 35 प्रतिशत भारतीय शहरों में वार्षिक पीएम 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 10 गुना अधिक है।

असम और मेघालय की सीमा पर स्थित शहर बर्नीहाट में प्रदूषण का उच्च स्तर स्थानीय कारखानों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण है, जिसमें शराब निर्माण, लोहा और इस्पात संयंत्र शामिल हैं। दिल्ली साल भर उच्च वायु प्रदूषण से जूझती है और सर्दियों में यह समस्या और भी बदतर हो जाती है जब प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, धान की पराली जलाने, पटाखे फोड़ने से निकला धुआं और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोत मिलकर हवा की गुणवत्ता को खतरनाक बना देते हैं।

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की उम्र अनुमानित 5.2 वर्ष कम हो रही है। पिछले साल प्रकाशित 'लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ' अध्ययन के अनुसार, 2009 से 2019 तक भारत में हर साल लगभग 15 लाख लोगों की मौत संभावित रूप से दीर्घकाल तक पीएम 2.5 प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण हुई। पीएम 2.5, 2.5 माइक्रोन से छोटे वायु प्रदूषण कणों को संदर्भित करता है, जो फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में समस्या, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत ने वायु गुणवत्ता डेटा संग्रह में प्रगति की है, लेकिन पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है।उन्होंने कहा, ''हमारे पास डेटा है, अब हमें कार्रवाई की आवश्यकता है। कुछ समाधान आसान हैं जैसे जीवाश्म ईंधन को एलपीजी से बदलना। भारत के पास इसके लिए पहले से ही एक योजना है, लेकिन हमें अतिरिक्त सिलेंडरों पर और सब्सिडी देनी चाहिए। पहला सिलेंडर मुफ्त है लेकिन सबसे गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को अधिक सब्सिडी मिलनी चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और बाहरी वायु प्रदूषण कम होगा।''

गंगा को ही धोखा देती रही मोदी सरकार

न्यूज़ डेस्क

क्या गंगा सफाई करने और गंगा को पवित्र करने के नाम पर मोदी सरकार मां गंगा के साथ ही छल करते रहे और धोखा देते रहे और गंगा के नाम पर सनातनी वोट को लुटते रहे? कोई भक्त सनातनी और अंधभक्त अगर इसे सुने तो उसे गुस्सा आ सकता है लेकिन सच को कोई झुठला भी तो नहीं सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों नामानि गंगे योजना की सच्चाई को देश के सामने रखकर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी है। खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी ने गंगा सफाई के नाम पर मां गंगा से केवल धोखा किया, पैसे तो खूब जुटाए, पर खर्च नहीं किया। खड़गे ने इसके पक्ष में आंकड़े भी पेश किये हैं ताकि अंधभक्तो की आंखे खुल जाये। खड़गे ने कहा कि

करीब 11 साल पहले, 2014 में, नमामि गंगे योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना में मार्च 2026 तक 42,500 करोड़ का फंड इस्तेमाल किया जाना था, पर संसद में दिए गए प्रश्नों के जवाब से पता चलता है कि दिसंबर 2024 तक केवल 19,271 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं। यानी मोदी सरकार ने नमामि गंगे योजना का 55 प्रतिशत धन खर्च ही नहीं किया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 'नमामि गंगे' योजना के तहत आवंटित धन की 55 प्रतिशत राशि खर्च नहीं की गयी जो इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई की अपनी गारंटी भुला दी और सफाई के नाम पर मां गंगा को केवल धोखा दिया। खड़गे ने 'एक्स' पर लिखा, ''मोदी जी ने कहा था कि उनको ''मां गंगा ने बुलाया है'' पर सच ये है कि उन्होंने गंगा सफ़ाई की अपनी गारंटी को भुलाया है।''

कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि मां गंगा के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? उन्होंने कहा, ''2015 में मोदी जी ने हमारे एनआरआई साथियों से 'स्वच्छ गंगा कोष' में योगदान देने का आग्रह किया था। मार्च, 2024 तक इस इस कोष में 876 करोड़ रुपये दान दिए गए, पर इसका 56.7 प्रतिशत हिस्सा अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस फंड का 53 प्रतिशत सरकारी उपक्रमों से दान लिया गया है।'' खड़गे ने दावा किया, '' नवंबर, 2024 में राज्य सभा में दिया गया एक उत्तर बताता है कि नमामि गंगे की 38 प्रतिशत परियोजनाएं अभी लंबित हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने के लिए कुल आवंटित धन का 82 प्रतिशत ख़र्च किया जाना था पर 39 प्रतिशत एसटीपी अभी भी पूरे नहीं हुए हैं और जो पूरे हुए हैं वो चालू ही नहीं हैं।''

उनके मुताबिक, नवंबर 2024 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा की सफाई बनाए रखने में प्रशासन की विफलता पर कड़ी नाराजगी जताई थी और कड़ी फटकार लगाते हुए सुझाव दिया था कि नदी के किनारे एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें लिखा हो कि शहर में गंगा का पानी नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है।

वोटर आईडी डुप्लीकेसी : सामने आया चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र!

न्यूज़ डेस्क

वोटर आईडी डुप्लीकेसी और वोटर आईडी में गड़बड़ी को लेकर जहाँ देश के भीतर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर हमलावर है ,चुनाव आयोग फंसता नजर आ रहा है। अब चुनाव आयोग के सामने समस्या यह है कि वह करे क्या ? उसके पहले के बयान को अगर सही माना जाए तो वोटर आईडी में कोई गड़बड़ी नहीं है और गड़बड़ी हो भी नहीं सकता। और चुनाव आयोग के हालिया बयान को सही माना जाए तो उसके पहले के बयान गलत थे और झूठ से भरे थे। देश को गुमराह करने वाले थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर खुद चुनाव आयोग के पुराने बयान को शेयर करके चुनाव आयोग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है ये खुलासा कांग्रेस के ईगल ग्रुप ने किया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है कि 2008 में खुद चुनाव आयोग ने कहा था कि हर वोटर कार्ड यूनिक है और इसमें डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस ने कुछ ऐसा बताया है कि जिससे खुद चुनाव आयोग ही घिर गया है।

कांग्रेस ने लिखा-18 सितंबर, 2008 को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया कि "मतदाता पहचान पत्र यूनीक हैं। हालांकि, चुनाव आयोग आज कहता है कि डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा 'दशकों पुराना मुद्दा' है। भारत के नागरिकों को चुनाव आयोग के किस बयान पर विश्वास करना चाहिए? आज एक औसत भारतीय मतदाता को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों करना चाहिए? कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह यानी ईगल ने एक बयान में कहा, "कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग द्वारा दिए गए इस कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग दोहराती है।" बता दें कि ईगल एक आठ सदस्यीय समिति है, जिसे चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की निगरानी के लिए कांग्रेस द्वारा गठित किया गया है। ईगल ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने एक ही मतदाता पहचान पत्र को कई मतदाताओं को आवंटित किए जाने के मुद्दे पर दोहरा जवाब दिया है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं के पीछे छिपकर एक कमजोर स्पष्टीकरण दिया है। आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि उसकी मतदाता सूचियों में गलतियां हैं वो भरोसेमंद नहीं हैं। यानी देखा जाए तो वोटर आईडी में डुप्लीकेसी के मामले में विपक्ष ने चुनाव आयोग को बुरी तरह से घेर लिया है।

वोटर आईडी में गड़बड़ी की कहानी कई राज्यों से आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी यह कहानी सामने आयी है और टीएमसी ने इस मुद्दे पर कडा ऐतराज जताया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र चुनाव से लेकर दिल्ली और हरियाणा में भी वोटर आईडी में गड़बड़ी की बात सामने आयी है और इसकी शिकायत भी की गई है। लोकतंत्र की नींव चुनावी प्रक्रिया पर ही निर्भर है। लेकिन अगर गलत तरीके से चुनाव कराने की परिपाटी शुरू होती है तो लोकतंत्र की सभी बातें नष्ट हो जाती है। ऐसे में अब चुनाव आयोग क्या कुछ करता है इसे देखने की बात होगी। इतना तो साफ़ हो गया है कि पिछले कुछ सालों में देश के चुनाव आयोग का इकबाल कमजोर हुआ है और अब उस पर जो लांछन लग रहे हैं वह लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। चुनाव आयोग को अपने बारे में समीक्षा करने की जरूरत है।

भाषा विवाद :तमिलनाडु ने राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह को किया अस्वीकार

न्यूज़ डेस्क

भाषा का विवाद अब दक्षिण भारत में बढ़ता ही जा रहा है। तजा मामला यह है कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य के बजट 2025 में आधिकारिक रुपया ( ) चिन्ह को हटाने का फैसला किया है। इसकी जगह अब तमिल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह को अस्वीकार किया है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ तमिलनाडु सरकार के विरोध के अगले कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब इस विरोध को लेकर केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है यह देखना बाकी है। यह फैसला केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी थोपने के विवाद के बीच लिया गया है।तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू की गई तीन-भाषा नीति को लागू करने से इनकार किया है। इसके चलते केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान यानी एसएसए के तहत मिलने वाली 573 करोड़ रुपये की सहायता राशि रोक दी है। नीति के नियमों के अनुसार, एसएसए फंडिंग का 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और इसके लिए राज्यों को नई शिक्षा नीति 2020 के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। लेकिन डीएमके सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी सीखने का दबाव बना रही है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डीएमके सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध तमिल भाषा, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है।यह विवाद केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच बढ़ते टकराव को दिखाता है, जो नई शिक्षा नीति और हिंदी भाषा को लेकर लंबे समय से जारी है। बता दें कि 2010 के केंद्रीय बजट के दौरान, तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भारतीय मुद्रा के लिए एक नया प्रतीक लाने की घोषणा की। यह प्रतीक भारत की संस्कृति और पहचान को दर्शाने वाला होना चाहिए। इसके लिए एक सार्वजनिक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कई डिजाइनों में से मौजूदा रुपये ( ) के प्रतीक को चुना गया।इसके बाद, इस नए प्रतीक को मुद्रा नोटों और सिक्कों में शामिल किया गया। पहली बार चिन्ह वाले सिक्के 8 जुलाई 2011 को जारी किए गए और ये आधिकारिक रूप से प्रचलन में आए।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी उड़ान असम्भव !

न्यूज़ डेस्क

बड़े ही शोरशराबे के साथ मोदी और योगी सरकार यह दावा करती रही है कि इस साल के अप्रैल महीने के पहले सप्ताह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के साथ ही खासकर यूपी में इसे खूब प्रचारित भी किया गया। कई बार पीएम मोदी भी ऐसा ही कुछ कहते रहे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उससे साफ़ है कि योगी का यह दावा झूठा साबित हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, एयरपोर्ट अब अप्रैल में शुरू नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो पाएगा, जिसके बाद कुछ जरूरी काम किए जाएंगे, जिसे करने में 10 मई तक समय लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक, अब 15 से 20 मई के बीच एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो पाएंगी। हालांकि इसमें भी संदेह ही है। इस डेट को लेकर भी अधिकारियों के बीच संशय बना हुआ है। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि मई में भी एयरपोर्ट शुरू होना मुश्किल है, जून के पहले सप्ताह तक उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है।

बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल में उड़ान शुरू करने की तैयारी थी। इसे लेकर युद्धस्तर पर एयरपोर्ट में काम चल रहा है। इसके बाद भी 30 अप्रैल तक काम पूरा नहीं हो पाएगा। जिसके बाद अधिकारियों ने मई में एयरपोर्ट शुरू कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बारे में फिलहाल यमुना अथॉरिटी सीईओ और दूसरे अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों को अप्रैल तक एयरपोर्ट का काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। किसी कारणवश काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद से अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि काम पूरा होने और जरूरी कागजी कार्रवाई में मई का पूरा महीना भी लग जाएगा, जिसके बाद जून में जाकर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक, वैट नाइन, बम निरोधक उपाय, आइसोलेटेड पार्किंग, रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, पानी, बिजली सप्लाई, कनेक्टिंग रोड, सोलर सिस्टम, अग्निशमन, वाइल्ड लाइफ सर्विस, मॉनिटरिंग सिस्टम, वॉच टावर, एप्रैन आदि की जांच की और पाया गया कि ये सभी काम पुरे हो गए हैं। लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग में इंटरनेशनल टर्मिनल का कार्य अभी अधूरा है। वायु प्रवाह की दिशा बताने के लिए एएनएस नेविगेशन उपकरण मार्च के अंत तक स्थापित हो जाएगा। अप्रैल में एयरपोर्ट के विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरोड्रोम लाइसेंस मिलने की उम्मीद है।

मुफ्त योजनाओं पर इनफ़ोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति ने किया हमला

राजनीतिक डेस्क

मुफ्त वाली रेवड़ी कल्चर पर इनफ़ोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति ने जो बयान दिया है वह मौजूदा सरकार पर भले ही एक करारा तमाचा है लेकिन बड़ी बात तो यह है कि क्या इस तमाचे का भी कोई हल सरकार के पास है ? पक्ष और विपक्ष की पूरी राजनीति केवल चुनाव और सरकार बनाने पर टिकी हुई है। इस खेल में जनता को केवल ठगने का उपक्रम किया जाता है। इस खेल में बस यही टारगेट होता है कि चाहे जैसे भी हो वह सत्ता सरकार के पास पहुंच जाए और देश का हाल चाहे जो भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें केवल पोलिटिकल पार्टियां से जिम्मेदार नहीं है। जनता भी कम लोभी नहीं है और। लोभी जनता को ठगने के लिए अब सभी पार्टियां और सरकार वह सब कुछ करने को तैयार है जिससे उसकी सत्ता कायम रहे।

इंफोसिस को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा है कि मुफ्त चीजों से नहीं घटेगी देश की गरीबी। उन्होंने कहा कि गरीबी तभी कम होगी जब इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के जॉब क्रिएशन करने होंगे। और फिर इससे गरीबी घटेगी। एक कार्यक्रम में नारायण मूर्ति ने एंटरप्रेन्योर्स से अधिक कंपनियां और कारोबार बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया और कहा कि अगर हम इनोवेटिव एंटरप्राइज बनाने में सक्षम हैं, तो गरीबी धूप वाली सुबह की ओस की तरह गायब हो जाएगी। मूर्ति का यह बयान ठीक वैसा ही जिसके बारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं। मोदी की सरकार को विपक्ष की आवाज को भला जरूरत क्यों ? मोदी सरकार को लगता है कि वह देश की काबिल सरकार है और वह जो कर रही है वही अंतिम सत्य है।

नारायण मूर्ति ने उद्यमियों के समूह को संबोधित करते हुए कहा कि "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों-हजारों नौकरियां पैदा करेगा और इसी तरह आप गरीबी की समस्या का समाधान करेंगे। आप मुफ्त उपहार देकर गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कोई भी देश इसमें सफल नहीं हुआ है।" आपको बता दें कि इन्फोसिस के को-फाउंडर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में मुफ्त में चीजें दिए जाने और उनकी लागत पर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि, बाद में नारायण मूर्ति ने स्पष्ट किया कि उन्हें राजनीति या शासन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने नीतिगत ढांचे के नजरिए से कुछ सिफारिशें की है।

नारायण मूर्ति ने कहा कि लाभ के बदले में स्थिति में सुधार का आकलन भी किया जाना चाहिए। हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली का उदाहरण देते हुए नारायण मूर्ति ने कहा कि राज्य ऐसे घरों में छह महीने के बाद सर्वे करके यह पता लगा सकते हैं कि बच्चे अधिक पढ़ रहे हैं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इन दिनों बेचे जाने वाले अधिकांश एआई सोल्यूशंस मूर्खतापूर्ण पुराने प्रोग्राम हैं, जिन्हें भविष्य के काम के रूप में प्रचारित किया जाता है। एआई में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्षमताएं शामिल हैं।

भारत में फ्री सुविधाओं की कई स्कीमों की वैल्यू सरकार के कई विभागों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। फ्री सुविधाओं का ऐलान मतलब पार्टी के लिए जीत की गारंटी। आजकल चुनावों में यह एक तरह से कल्चर बनता जा रहा है कि जो पार्टी जितनी मुफ्त सुविधाएं देगी, उस पार्टी का चुनाव जीतने का चांस उतना बढ़ जाएगा। इसके चलते सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब ने फ्री सुविधाओं की झड़ी सी लगा दी है क्योंकि आखिर चुनाव सभी को जीतना है। सरकार सबको बनानी है। पहले फ्री की सुविधाओं का ऐलान कुछ चीजों के लिए होता थी, लेकिन आज बस कुछ चीजें ही बची हैं, जिनको फ्री किया जाना बाकी रह गया है।

फ्री की सुविधा वोटरों को लुभाने के लिए एक शॉर्ट टर्म स्कीम होती है। जबतक उस पार्टी की सरकार है, स्कीम जिंदा है और चल रही है। सरकार गई स्कीम गई. कई बार इन फ्री की सुविधाओं की खामियाजा बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता है। फ्री सुविधाओं को हम पूरी तरह वेलफेयर स्कीम में नहीं रख सकते, क्योंकि यह शार्ट टर्म रिलीफ के तौर पर काम करती है। सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने मिड डे मील योजना की घोषणा की थी। इस स्कीम को 1956 में शुरु किया गया था. बाद में इसको केंद्र की सरकार ने पूरे देश में लागू किया। एन टी रामाराव ने सबसे पहले दो किलो फ्री राशन देने की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश का यह स्कीम आज नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का हिस्सा है।

1967 में डीएमके के फाउंडर सीएन अन्नादुरई ने चुनाव जीतने के लिए एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो 4.5 किलो चावल एक रुपये में देंगे। साल 2006 में डीएमके पार्टी की तरफ से वादा किया गया था कि अगर वह सरकार में आते हैं तो लोगों को फ्री कलर टीवी दिया जाएगा. बाद में इस तरह के वादे जमीन देने, लैपटॉप देने, साइकिल देने तक पहुंचे।

कोरोना से अब तक केंद्र सरकार का फ्री राशन हो, किसानों के लिए लोन माफी हो, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की सवारी, फ्री पढ़ाई या फ्री तीर्थयात्रा की सवारी हो. ये सब के सब अभी तक असरदार और कारगर साबित हुए हैं।अगर हम पिछले 8 विधानसभा चुनावों को देखें तो यह निकलकर सामने आता है कि मुफ्त रेवड़ियों ने राज्य के चुनावों पर अपना गहरा असर डाला है। अगर हम सिर्फ पांच योजनाओं का देखें तो इनमें- महिलाओं के मासिक भत्ता ने महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में अपना अहम रोल प्ले किया है। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह गेमचेंजर साबित हुआ है. मुफ्त बस यात्रा ने दिल्ली में आम आदमी की पार्टी को सरकार बनाने में अहम रोल प्ले किया है। फ्री बस सुविधा ने युवाओं और महिलाओं के वोटों को अपनी तरफ खींचा है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को मुख्यधारा में लाने की बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं तैयार कर रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा दिया जा रहा है। चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियों के एलान से देश की शीर्ष अदालत चिंतित हैं। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थी परिवार को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। किसान सम्मान निधि के तहत हर चार महीने में किसानों को 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। साल 2020 में केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलिंडर मुहैया करवाया जाता है। पीएम आवास योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। इस योजना में समाज के सबसे गरीब तबके को आवास दिया जाता है।इसके साथ ही अब हर राज्य में मुफ्त योजनाएं चल रही है।

फिर शुरू हुई जनगणना की सुगबुगाहट

न्यूज़ डेस्क

2021 में होने वाली देश की जनगणना अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है इसका जबाव सब ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक उत्तर का पता नहीं चला। पहले कोविद का बहाना बनाया गया था फिर भी अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया। यह बात और है कि सरकार के लोग हर बार यही कहते हैं कि जनगणना जल्द कराई जायेगी। लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। सरकार सभी काम करती रही है। दुनिया के बाकी देशों में भी कोविद के दौरान ही जनगणना कराई गई थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। जनगणना गृह मंत्रालय को कराना है। लेकिन अमित शाह अभी चुप है।

इधर एक बार फिर से जनगणना की सुगबुगाहट शुरू हुई है। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने ही अपनी रिपोर्ट में जल्दी से जल्दी जनगणना कराने को कहा है। इस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा के सांसद राधामोहन दास हैं। उन्होंने जनगणना जल्दी कराने के साथ साथ रोहिंग्या, बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की पहचान करके उनको देश से निकालने को भी कहा। गृह मामलों की संसदीय समिति ने 10 मार्च को अपनी रिपोर्ट दी है। सवाल है कि क्या भाजपा सांसद की अध्यक्षता और एनडीए के बहुमत वाली समिति ने ईमानदारी से जनगणना की जरुरत मानते हुए रिपोर्ट दी है या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार अभी तत्काल जनगणना कराने के मूड में नहीं है। अगले साल परिसीमन की तैयारी हो रही है। उससे पहले जनगणना जरूरी है। लेकिन संविधान का 84 वां संशोधन इसके रास्ते में बाधा है। सरकार उस बाधा को दूर करने के उपायों पर विचार कर रही है।

कोविद के बाद सारे कामकाज सुचारू रूप से हो रहे हैं लेकिन जनगणना नहीं हुई। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अब संसद की एक स्थायी समिति ने भी जल्दी से जल्दी जनगणना कराने को कहा है। हालांकि इस बारे में फैसला सरकार को करना है और वह कई चीजों को ध्यान में रख कर फैसला करेगी।

दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना भारत

न्यूज़ डेस्क

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुसरा हथियार आयातक देश के रूप में उभरा है। वैश्विक हथियार आयात में भारत क हिस्सा 8.3 फीसदी हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार रूस से हथियार आयात में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का धीरे-धीरे ज्यादा रक्षा आयात हो रहा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल से आपूर्ति में वृद्धि देखी जा रही है। यूक्रेन ने वैश्विक हथियार आयात का 8.8% हिस्सा हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 8.3% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। कतर और सऊदी अरब 6.8% हिस्सेदारी के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर और पाकिस्तान 4.6% हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर है। हालांकि रूस पर भारत की निर्भरता में गिरावट आई है, फिर भी रूस भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के साथ रक्षा सौदों में कमी आई है, खासकर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वैश्विक राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियां बदल गई हैं। इसके बावजूद, रूस और भारत के बीच पुराने रक्षा सौदों का असर अब भी देखने को मिल रहा है, और यह दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखता है।

रूस से आयात में कमी आने के बावजूद, भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल जैसे देशों से अपनी रक्षा आपूर्ति बढ़ाई है। इन देशों के साथ भारतीय रक्षा सहयोग में तेजी आई है, जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिका और फ्रांस से अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों, विमान और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति बढ़ी है, जिससे भारत के पास ज्यादा विविध और आधुनिक सैन्य क्षमताएं आ रही हैं। इसके अलावा, इज़राइल से भी भारत ने मिसाइल प्रणालियों, ड्रोन और अन्य उच्च तकनीकी रक्षा उपकरणों की खरीदारी की है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने विभिन्न देशों के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत किया है, जो उसे वैश्विक सैन्य संदर्भ में एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है। इसके अलावा, भारत अपनी आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहा है, और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है।

रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं, खासकर रक्षा क्षेत्र में। रूस ने हमेशा भारत को अपनी सैन्य जरूरतों के लिए सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण प्रदान किए हैं। हालांकि, अब भारत ने रूस से अपनी आयातित सैन्य सामग्री को कम करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। भारत अभी भी रूस से प्रमुख सैन्य उपकरणों जैसे टी-90 टैंक, विमान और अन्य रक्षा सामग्री खरीदता है। रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि भारत की रक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं और वह अब अपने रक्षा आयात में विविधता लाने की दिशा में काम कर रहा है। रूस से आयात में कमी आ रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत और रूस के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। इसके बजाय, भारत अब अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल जैसे देशों से अधिक तकनीकी और उन्नत सैन्य उपकरण प्राप्त कर रहा है, जिससे उसकी सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति मजबूत हो रही है।

चार नहीं चालीस विधायकों के नारे के साथ मैदान में उतरेगी वीआईपी

न्यूज़ डेस्क

बिहार में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह तो समय ही बताएगा लेकिन सभी पार्टियां अपने गठबंधन पर दबाव बनाने में जुटी हुई है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से भी राजद पर दबाव डाला जा रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी भी राजद और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस बार वीआईपी बिहार की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। वह कह रही है कि इस चुनाव में चार नहीं, 40 विधायक बनाना है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि जब 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तब 40 से 50 सीटों पर चुनाव जीतकर जरूर आएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील की।

विकासशील इंसान पार्टी की पिछले दिनों दो दिवसीय प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर में हुई बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कई अन्य प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।बैठक के बाद पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने निर्णयों के विषय में बताते हुए कहा, "पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है। पार्टी के साथ आठ से दस प्रतिशत वोट हैं। बिहार में वीआईपी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर हम परिणाम प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 60 सीटों पर लड़ेगी। शेष सीट हम सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे।"

उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम टिकट मांगने वाले नहीं, बांटने वाले हैं। हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो। हमारे लिए गठबंधन जरूरी है। उन्होंने सहयोगियों को भरोसा देते हुए कहा कि जहां पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे, वहां हम उन्हें जीत दिलाने में मदद करेंगे। महागठबंधन में शामिल वीआईपी के प्रमुख सहनी ने यह भी कहा कि 50 प्रतिशत सीटें हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी के लिए सुरक्षित करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि आपकी जीत पर हमारे सिर पर ताज होगा। ताज जब होगा तभी बिहार में निषाद समाज का कल्याण होगा। हमारी सरकार बनने पर वीआईपी का उप मुख्यमंत्री होगा।

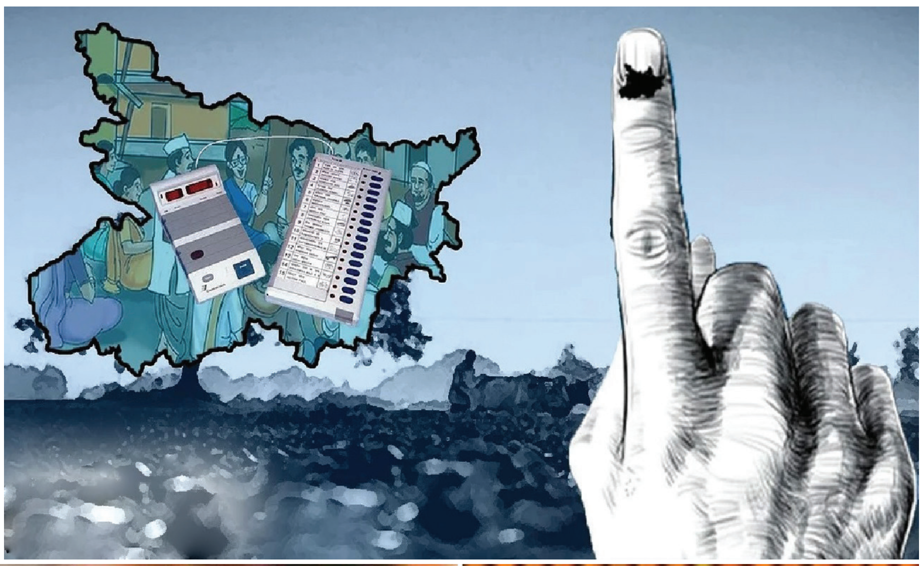

महागठबंधन में शामिल वीआईपी के प्रमुख सहनी ने यह भी कहा कि 50 प्रतिशत सीटें हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी के लिए सुरक्षित करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि आपकी जीत पर हमारे सिर पर ताज होगा।

क्या कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा महागठबंधन?

न्यूज़ डेस्क

बिहार में इस बार कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। बड़े स्तर पर प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल जारी है तो पार्टी के नए बिहार प्रभारी बीजेपी के स्लीपर सेल बन चुके कोंग्रेसियों पर हमला भी कर रहे हैं और उन्हें हटाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस बार के बिहार चुनाव में कांग्रेस दो बड़े चेहरे पर दांव लगाने जा रही है। एक चेहरा है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और दूसरे हैं युवा नेता कन्हैया कुमार। कहा जा रहा है कि पार्टी कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में भी उतारने जा रही है। कन्हैया कुमार अब बिहार की दौरा पर जा रहे हैं और रोजगार की मांग के साथ बिहारी युवाओं को अपने साथ समेटने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिहार में इस बार कांग्रेस हालांकि कुछ नए अंदाज में चुनाव लड़ने को तैयार है। पहली बात तो यह है कि युवा और मजबूत संगठन के सहारे कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और दूसरी बात यह है कि दलित ,पिछड़ों और मुस्लिम युवाओं पर उसका ज्यादा फोकस है। इसी समाज से आने वाले युवाओं पर कांग्रेस ज्यादा दांव लगा सकती है।

इधर एक नयी कहानी से महागठबंधन के भीतर हलचल मच गई है। यह कहानी पप्पू यादव की तरफ से कांग्रेस ने कहलवाई है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बेगूसराय में मीडिया से बातचीत के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला लिया जाएगा। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और सभी नेताओं के बीच चर्चा के बाद ही यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पप्पू यादव ने कहा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, यह बाद में तय होगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू जी, माले और प्रियंका गांधी जैसे नेता इस पर चर्चा करेंगे और चुनाव के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पप्पू यादव ने महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित करने पर भी सवाल उठाए और कहा कि मैं नहीं समझता कि महागठबंधन में किसी को भी नेता घोषित कर चुनाव लड़ने की परिपाटी रही है। गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी और चुनाव में उसकी बड़ी भूमिका रहेगी।

बिहार में हाल ही में हुए बागेश्वर बाबा के दौरे पर पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे बाबाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बागेश्वर बाबा दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और नटवरलाल है, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि यह बाबा लोगों को धोखा दे रहे हैं और ऐसे तत्वों को समाज में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलना चाहिए।

आखिर झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता मरांडी बन ही गए

न्यूज़ डेस्क

झारखंड में आखिर प्रतिपक्ष बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की नियुक्ति कर दी गई। यह नियुक्ति पिछले साढ़े तीन महीने से पेंडिंग थी और बीजेपी के भीतर कई नेता इस पद को पाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अंतिम जीत अब मरांडी की ही हुई है। अब वे सदन में प्रतिपक्ष के नेता हो गए हैं। बीजेपी को इस बड़े नेता से काफी उम्मीद भी है। मरांडी अब पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं यह देखने की बात होगी।

पिछले दिनों रांची के हरमू रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षकों भूपेंद्र यादव और के. लक्ष्मण की मौजूदगी में हुई विधायकों की बैठक में मरांडी के नाम पर सर्वसम्मति बनी।इसके साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर पिछले साढ़े तीन महीनों से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। नेता चुने जाने के बाद मरांडी ने कहा कि उन्हें पार्टी के नेतृत्व और विधायकों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए वह आभारी हैं। उन्होंने कहा, "अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ सदन के अंदर और बाहर दल को मजबूत बनाने के लिए हर पल कार्य करूंगा। संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। सबको साथ लेकर चलूंगा।"

मरांडी ने इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव, के. लक्ष्मण, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र राय सहित सभी साथी विधायकों का आभार जताया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं, पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों के साथ जनता की आवाज बनकर गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए पूर्ण निष्ठा और क्षमता के साथ कार्य करूंगा।" मरांडी ने कहा कि विधानसभा के पिछले कार्यकाल में भी पार्टी के विधायकों ने उन्हें नेता चुना था, लेकिन स्पीकर ने दुर्भावना से ग्रस्त होकर चार साल तक मामले को लटकाकर रखा। इसके बावजूद पार्टी के हम सभी विधायकों ने जनता के मुद्दों पर लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्य की सरकार के गलत कार्यों का जमकर विरोध किया।

मरांडी ने इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव, के. लक्ष्मण, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र राय सहित सभी साथी विधायकों का आभार जताया।

न्यू देहली पोस्ट

मोहन सरकार के बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं

न्यूज़ डेस्क

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पिछले बुधवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह बजट 4 लाख 21 हजार करोड़ से ज्यादा का है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा आम बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया है और न ही पुराने कर में कोई बदलाव किया गया है। इस तरह राज्य में कोई भी सामान सस्ता या महंगा नहीं होगा।

राज्य सरकार का यह बजट युवा, किसान, गरीब और नारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन सभी के कल्याण के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। इस बजट में 'लाडली बहन योजना' के लिए 18,500 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया। साथ ही इसे अटल पेंशन योजना से भी जोड़ने की बात कही गई है।

इस बजट में कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग के आधार पर महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण 1 अप्रैल से किया जाएगा। इसके साथ ही मजरा टोला को सड़क से जोड़ने के लिए प्रावधान किए गए हैं। एक लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, वहीं 500 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश बजट में शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत 22 आईटीआई संस्थान और डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। वहीं, तीन लाख नौकरियां भी मिलने के आसार हैं। इस बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है, इतना ही नहीं पुराने कर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भाजपा सरकार ने एक ओर बजट को राज्य के लिए विकास वाला बजट बताया है तो वहीं, विपक्ष ने इसे छलावा भरा बजट करार दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट को कर्ज वाला बताया है।

मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह बजट नहीं, मध्यप्रदेश को कर्ज/भ्रष्टाचार में डुबोने का दस्तावेज है। भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को फिर से एक छलावा भरा बजट दिया है। इस बजट में विकास की कोई ठोस योजना नहीं है, बल्कि इसे कर्ज बढ़ाने, कमीशनखोरी को संस्थागत करने और भ्रष्टाचार को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायक दल के साथ मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की लापरवाही और कर्ज लेने की आदत ने आम जनता को कर्ज की जंजीरों में जकड़ दिया है। हर व्यक्ति पर 55,000 रुपये से ज्यादा का कर्ज थोप दिया गया है, और सरकार बेशर्मी से कर्ज लेकर घी पी रही है। आम आदमी का हाल बेहाल है, वो कर्ज के बोझ तले दबकर रह गया है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। ये सरकार नहीं, जनता को लूटने वाली सत्ता है। अब समय आ गया है कि इस कर्ज की मार से जनता को बचाया जाए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह बजट नहीं, मध्यप्रदेश को कर्ज/भ्रष्टाचार में डुबोने का दस्तावेज है। भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को फिर से एक छलावा भरा बजट दिया है। इस बजट में विकास की कोई ठोस योजना नहीं है, बल्कि इसे कर्ज बढ़ाने, कमीशनखोरी को संस्थागत करने और भ्रष्टाचार को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। यह बजट भाजपा सरकार की असफलताओं और जनविरोधी नीतियों की पोल खोलता है।

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होंगे मध्यप्रदेश के चार स्थल

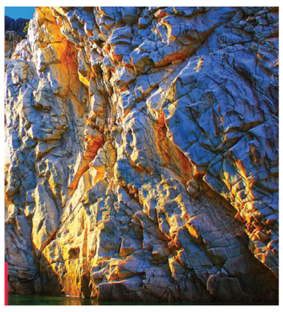

न्यूज़ डेस्क

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक मान्यता मिली है, क्योंकि इसके चार स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आगे शामिल करने के लिए इसकी संभावित सूची में शामिल किया गया है। पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के 4 सहित भारत के कुल 6 ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। सीएम यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य ने विश्व मंच पर अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में एक और उपलब्धि हासिल की है, जिसमें अशोक शिलालेख स्थल, चौंसठ योगिनी मंदिर, गुप्त काल के मंदिर और बुंदेलों के महल-किले को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, जो भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य में मध्य प्रदेश के विशिष्ट स्थान को दर्शाता है। " मुख्यमंत्री ने कहा, "यह मान्यता राज्य की अपनी अमूल्य विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ' दरअसल, पिछले साल यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को भी अपनी संभावित सूची में शामिल किया था। इसमें ग्वालियर किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, चंबल घाटी के रॉक आर्ट साइट्स, भोजपुर में भोजेश्वर महादेव मंदिर, मंडला में रामनगर के गोंड स्मारक और धामनार का ऐतिहासिक समूह शामिल हैं। "

यूनेस्को के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में अब मान्यता प्राप्त विरासत स्थलों की संख्या 18 हो गई है। इनमें तीन स्थायी सूची में (खजुराहो मंदिर समूह, भीमबेटका रॉक शेल्टर और सांची के बौद्ध स्मारक) और 15 संभावित सूची में हैं। संभावित सूची में अन्य स्थलों में मांडू के स्मारक, ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भेड़ाघाट-लमेटाघाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भारत का प्रतिष्ठित साड़ी-बुनाई समूह चंदेरी शामिल हैं। एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह सम्मान विरासत संरक्षण और सतत पर्यटन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, संस्कृति विभाग, पुरातत्वविदों, इतिहास के प्रति उत्साही लोगों, संगठनों और नागरिकों को बधाई दी है, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों से इन ऐतिहासिक खजानों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट होने का आह्वान किया है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य का सांस्कृतिक गौरव वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर बढ़ता रहे।

आबकारी घोटाले में कांग्रेस नेता कवासी लखमा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

न्यूज़ डेस्क

छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाला को लेकर राजनीति फिर से कुलांचे मार रही है। हालिया घटना ये है कि प्रदेश में हुए शराब घोटाला में ईडी ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के साथ ही एक दर्जन शराब निर्माताओं के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किया है। बता दें कि 2161 करोड़ के शराब घोटाले में अब तक 21 लोगों को आरोपित किया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता कवासी पिछले दो माह से रायपुर जेल में बंद हैं। रायपुर जेल में बंद होटल कारोबारी अनवर ढेबर के आवेदन पर कोर्ट ने डिस्टलरियों को आरोपित बनाया है। आरोप पत्र में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ डिस्टलरी को 48, भाटिया वाइन मर्चेंट को 28 और वेलकम डिस्टलरी को 24% दुकानों में शराब आपूर्ति का काम दिया गया था।

आरोप पत्र में दावा किया गया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हर महीने दो करोड़ रुपये कमीशन के तौर पर दिए जाते थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तीन साल तक यह सिलसिला चला। 36 महीने में प्रोसीड ऑफ क्राइम 72 करोड़ रुपये का है इन पैसों से सुकमा में कवासी के बेटे हरीश लखमा ने घर और कोंटा में कांग्रेस भवन का निर्माण कराया है। इस मामले में पहले से जेल में बंद अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पास हर महीने कमीशन पहुंचता था।

अरविंद सिंह ने बताया है कि शराब कर्टल से हर महीने लखमा को 50 लाख रुपये दिए जाते थे। यही नहीं 50 लाख रुपये के ऊपर भी 1.5 करोड़ रुपये और दिया जाता था। इस हिसाब से दो करोड़ रुपये पूर्व आबकारी मंत्री को हर महीने कमीशन के तौर पर मिलते थे।प्रदेश में हुए शराब घोटाले मामले में ईडी ने अपनी चार्टशीट में बताया था कि घोटाले में 1,200 करोड़ रुपये की राशि शराब निर्माता कंपनियों ने कमाए हैं।

जिन शराब निर्माताओं को इस मामले में आरोपित किया गया है उनमे शामिल हैं -कंपनी भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड,छत्तीसगढ़ डिस्टलरी,वेलकम डिस्टलरी,मेसर्स नेक्स्ट जेन,दिशिता उद्यम,ओम सांई वेबरेज। इसके साथ ही सिद्धार्थ सिंघानिया, कारोबारी,मेसर्स टाप सिक्योरिटी के मालिकों के साथ नवीन केडिया,भूपेंद्र सिंह भाटिया, कारोबारी,राजेंद्र जायसवाल, कारोबारी,आईएएस निरंजन दास,रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी। आरोपी लोगों में कवासी लखमा, पूर्व मंत्री,अनवर ढेबर, कारोबारी,अरविंद सिंह, कारोबारी और विजय भाटिया, कारोबारी भी शामिल है।

आबकारी विभाग के अधिकारी इकबाल खान और जयंत देवांगन पैसों की व्यवस्था करके कवासी तक भिजवाते थे। कन्हैया लाल कुर्रे के माध्यम से पैसों के बैग जमा किए जाते थे। यहां तक कि कवासी ने स्वयं अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि अरुण पति त्रिपाठी उनके कागजों पर हस्ताक्षर करवाता था। ऐसे में उन्हें जानकारी थी कि विभाग में बड़ा खेल चल रहा है, इसलिए इस मामले में इनकी संलिप्तता साफ तौर पर दिखाई दे रही है।

शराब घोटाले में शराब निर्माता कंपनियों में नकली शराब बनाने से लेकर, फर्जी होलोग्राम लगाने का काम किया जाता था। वहीं, प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ की डिस्टिलरियों को नकली होलोग्राम उपलब्ध कराए थे। इन होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था। इससे लगभग 1,200 करोड़ रुपये कमाए हैं।

कैग का खुलासा : खट्टर सरकार ने लगाई थी खजाने में 1000 करोड़ की सेंध

न्यूज़ डेस्क

जेपी की मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली पूर्व हरियाणा सरकार के कार्यकाल की आई कैग रिपोर्ट में राज्य के खजाने को बड़ी चपत बताई गई है। ये आंकड़ा 11000 करोड़ से अधिक का है। बिक्री कर, वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस को लेकर 2021-22 की आई कैग की इस रिपोर्ट में राज्य के खजाने को हुए नुकसान के लिए खट्टर सरकार के कु-प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया है।

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन 10 मार्च को सदन के पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में राज्य के खजाने को हुए नुकसान का दिया गया आंकड़ा बड़ा है। कैग ने लिखा है कि बिक्री कर, वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के 104 यूनिटों के अभिलेखों की 2021-22 के दौरान की गई सैंपल जांच में 2,552 मामलों में 1,103,94 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। संबंधित विभागों ने 1,077 मामलों में 643,07 करोड़ की हानि तथा अन्य कमियां स्वीकार की हैं। अब बड़ा सवाल तो यही है कि कैग की रिपोर्ट के सहारे राजनीति को चमकाने वाली बीजेपी और उसके शीर्ष नेता क्या हरियाणा की अपनी पूर्व सरकार को दण्डित कर पाएगी ? ऐसा लगता तो नहीं क्योंकि बीजेपी ऐसा नहीं करती है। नैतिकता और आचरण उसे नहीं भाती।

आगे हरियाणा की पूर्व सरकार पर आयी कैग की रिपोर्ट पर और भी बात की जाएगी लेकिन पहले कैग की रिपोर्ट को आधार बनाकर इस देश में कैसे -कैसे खेल हुए हैं उस पर चर्चा जरुरी है। बता दें कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर देश में केंद्र की सरकार भी जा चुकी है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार के जाने के कई और भी कारण हो सकते हैं लेकिन उसमे बड़ा कारण कैग की रिपोर्ट भी थी। कैग ने तब कई घोटाले का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। इसी रिपोर्ट में टू

जी घोटाले की कहानी को आगे बढ़ाया गया था और कहा गया था कि इससे सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ का नुक्सान सरकार को हुआ था। बीजेपी वाले इस कथित घोटाले के पीछे पड़ गए थे। देश भर में ऐसा हंगामा मचाया गया मानो देश को यूपीए सरकार ने लूट लिया। सामने लोकसभा चुनाव था। एक तरफ बीजेपी इस मामले को आगे बढ़ा रही थी तो दूसरी तरफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आंदोलन शुरू किया गया जिसका नेतृत्व अरबिंद केजरीवाल और उनकी मंडली कर रही थी। अन्ना हजारे को इस आंदोलन से जोड़ा गया और महीने भर तक दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल मजमा जमाया गया। लग रहा था मानो देश दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रही हो। कहते हैं कि संघ और बीजेपी ने मिलकर इस आंदोलन को धार देने का काम किया था और परिणाम यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लगभग साफ़ हो गयी। 44 सीटों पर सिमट गई। यह बात और है कि बाद के दिनों में तब के कैग ने महाराष्ट्र के अदालत में कहा कि यह कोई घोटाला नहीं था केवल एक अनुमान भर था। इस कार्य के लिए कैग ने अदालत में माफ़ी भी मांग ली थी।

केंद्र में मोदी की अगुवाई में सरकार बनी जो आज भी चल रही है। लगातार तीन बार मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे हैं। इन पिछले 11 सालों में कैग की किसी भी रिपोर्ट पर कोई हंगामा नहीं हुआ। कह सकते हैं कि किसी भी कैग की रिपोर्ट आयी भी या नहीं। लम्बे समय के बाद दिल्ली आबकारी मामले को लेकर कैग की एक रिपोर्ट आयी। जो केजरीवाल बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके सरकार को हारने का काम किया उसी कैग रिपोर्ट में वे जेल भी गए ,कई मंत्री भी जेल गए और बड़ी बात यह कि उनकी सरकार दिल्ली से भी विदा हो गई। आप को कैग के आधार पर ही बीजेपी ने दिल्ली से आउट कर दिया। अब दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी विराजमान है।

अब फिर कैग की बात। खट्टर सरकार से जुडी कैग रिपोर्ट बिंदुवार कहती है कि कर योग्य वस्तुओं के बजाय कर मुक्ति बिक्री कर के रूप में कटौती की अनुमति दे दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 4.99 करोड़ के कर का नुकसान हुआ। इसके अलावा 4.77 करोड़ के ब्याज की वसूली भी होनी थी। अधिकारियों ने 36.61 करोड़ के बजाय 27.97 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर पर कर की राशि तय की, जिससे 0.94 करोड़ के कर की हानि हुई। यही नहीं स्टॉक हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी दावे को गलत वापस कर दिया, जिससे भी 28.04 लाख की कम इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी हुई। रिपोर्ट में सिलसिलेवार बताते हुए लिखा गया है कि विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग को सत्यापित करने के लिए उचित तंत्र स्थापित नहीं किया। जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट, निष्पादित देयताओं और टर्न ओवर का मिलान न होने और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम का पालन न होने से 678.22 करोड़ की विसंगतियां हुईं। अजर भी कई तरह की विसंगतियों की चर्चा कैग रिपोर्ट में की गई है। कैग की रिपोर्ट बता रही है कि कुल 11 सौ करोड़ से ज्यादा की राजकोषीय छति खट्टर सरकार के काल में हुई है।

राज्य उत्पाद शुल्क को लेकर हुए ऑडिट में पाया गया है कि अवैध शराब के लिए अपराधियों से पेनल्टी वसूलने व आवंटियों से लाइसेंस फीस और ब्याज वसूलने की पहल नहीं गई, जिससे 7.46 करोड़ के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के अंतर्गत कर प्रबंधन के ऑडिट में भी बिंदुवार खामियां गिनाई गई हैं। इसमें बताया गया है कि सेल डीड को गलत वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप 19.91 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई। खून के रिश्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में ट्रांसफर डीड के 20 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राजकोष को 32.05 लाख के राजस्व की हानि हुई। पंजीकरण प्राधिकारियों ने पार्टियों के बीच सहमति की अपेक्षा 9 ट्रांसफर डीड का कम मूल्यांकन किया। इससे 12.27 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई। किसानों को 50 मामलों में स्टाम्प शुल्क से छूट की अनुमति दी गई थी। हालांकि, उन्होंने प्राप्त मुआवजे से आवासीय या व्यावसायिक भूमि खरीदी थी। इसके परिणामस्वरूप 1.61 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस की कम वसूली हो पाई।

थानेदार का बेटा ही डिजिटल अरेस्ट से की एक करोड़ की ठगी

न्यूज़ डेस्क

राजस्थान की श्रीगंगानगर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 1.05 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रवि गुर्जर है, जो जयपुर के सांगानेर स्थित शिव कॉलोनी का निवासी है। दिलचस्प बात यह है कि रवि के पिता आसाराम वर्तमान में चिड़ावा थाने में थानाअधिकारी के पद पर तैनात हैं और इससे पहले वे साइबर थाना में भी सेवाएं दे चुके हैं। साइबर डीएसपी कुलदीप वालिया के बताया कि सबसे पहले पुलिस टीम ने टेक्निकल रिर्सोसेज का यूज करते हुए ठगी के लिए इस्तेमाल हुए बैंक खातों की पहचान की और फिर जयपुर व भोपाल में छापामारी की। इसी जांच के दौरान रवि गुर्जर का नाम सामने आया, जिसके बैंक खाते में 9.93 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे। पूछताछ में रवि ने स्वीकार किया कि उसे अपने खाते में राशि जमा करवाने के लिए 15,000 रुपये दिए गए थे।

यह ठगी 15 नवंबर 2024 को हुई थी, जब अज्ञात आरोपियों ने चूनावढ़ निवासी एक व्यक्ति को वीडियो कॉल कर खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उन्होंने धमकी दी कि उसके बैंक खाते में अवैध रूप से धनराशि जमा हुई है और दिल्ली में उसके खिलाफ मामला दर्ज है। 7 साल की सजा का डर दिखाकर आरोपियों ने पीड़ित को मानसिक दबाव में लिया और उसे डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खाते की पूरी जानकारी ले ली। इसके बाद ठगों ने 1,05,59,960 रुपये अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित को आधे घंटे तक इस डिजिटल गिरफ्तारी में रखा गया, जिसके बाद जब उसे ठगी का अहसास हुआ तो उसने अपनी पत्नी को जानकारी दी। पीड़ित की पत्नी ने 16 नवंबर 2024 को साइबर थाना में मामला दर्ज कराया।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह का मुख्य संचालक भोपाल निवासी पीयूष नायक था। उसने डिजिटल अरेस्ट की इस योजना को अंजाम देने के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार किया था, जिसमें कई बैंक खाते और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया था। पुलिस जांच के दौरान यह भी पता चला कि महाराष्ट्र में हुई कई ठगी की वारदातों में भी रवि गुर्जर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और मामले की गहराई से जांच जारी है।

खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की 54 दिन की छुट्टी मंजूर

न्यूज़ डेस्क

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को केंद्र सरकार ने सूचित किया कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को लोकसभा सत्र के दौरान 54 दिनों की छुट्टी दी गई है। यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ के समक्ष दी गई। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों की छुट्टी के मामलों की जांच के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन और अधिवक्ता धीरज जैन ने अदालत को 11 मार्च को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया। इसमें अमृतपाल सिंह को 24 जून से 2 जुलाई, 22 जुलाई से 9 अगस्त और 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक की अनुपस्थिति की अनुमति दी गई है। अदालत ने इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की संसद से निष्कासन को लेकर व्यक्त की गई आशंका अब दूर हो गई है। इसके अलावा, अमृतपाल सिंह की लोकसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत अधिकारियों और मंत्रियों से मिलने की अनुमति की मांग पर अदालत ने कहा कि यह विषय संसद के नियमों के अधीन आता है, इसलिए उन्हें लोकसभा अध्यक्ष को इस संबंध में औपचारिक अनुरोध भेजना चाहिए।

बता दें कि अमृतपाल सिंह, जो 'वारिस पंजाब दे' संगठन के नेता हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. बैंस के माध्यम से अदालत में याचिका दायर कर संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। उनका तर्क था कि उनकी लंबी अनुपस्थिति न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं को भी प्रतिनिधित्व से वंचित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी गैरहाजिरी 60 दिनों से अधिक होती है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है। उन्होंने 30 नवंबर 2024 को लोकसभा अध्यक्ष को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि वह पहले ही 46 दिनों की गैरहाजिरी पूरी कर चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को भी पत्र भेजा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने न्यायालय का रुख किया।

हरियाणा की आबादी तीन करोड़ में से दो करोड़ बीपीएल!

न्यूज़ डेस्क

तीन करोड़ की आबादी में दो करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। किसी को भी सुनने में आश्चर्य हो सकता है लेकिन आंकड़े तो यही कह रहे हैं और सच्चाई भी यही है। यह तस्वीर है हरियाणा राज्य की। यह राज्य कृषि आधारित राज्य तो है ही ,पिछले कुछ सालों में इस राज्य में काफी उद्योग भी लगे हैं। राज्य के कई जिले अति आधुनिक है और काफी विकसित भी। लेकिन यहाँ के लोगों की माली हालत इतनी ख़राब हो गई है यह शायद केंद्र सरकार को भी पता नहीं है। करीब तीन करोड़ की जनसंख्या वाले हरियाणा में बीपीएल परिवारों की संख्या 51 लाख से पार हो चुकी है। एक परिवार में औसतन चार व्यक्तियों की संख्या को आधार माना जाए तो प्रदेश में दो करोड़ से अधिक लोग बीपीएल की श्रेणी में आ चुके हैं। हरियाणा में बीपीएल की संख्या को लेकर पिछले कई माह से विवाद चल रहा है।

सूचना विभाग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। कांग्रेस विधायक पूजा ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से पांच साल की रिपोर्ट मांगी। कांग्रेस विधायक ने पांच वर्ष में बीपीएल की संख्या तथा सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों पर जवाब मांगा। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इसके जवाब में बताया कि वर्ष 2020-21 में प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या आठ लाख 67 हजार 328 थी। वर्ष 2021-22 में बीपीएल की संख्या बढ़कर आठ लाख 78 हजार 329 हो गई। इसके बाद सरकार ने प्रदेश में नागरिक संसाधन सूचना विभाग का गठन किया। जिसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़कर 32 लाख 69 हजार 29 तक पहुंच गई।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में हरियाणा में बीपीएल परिवारों की संख्या 44 लाख 91 हजार 12 तक पहुंच गई। क्रिड की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा में बीपीएल परिवारों की संख्या 51 लाख 83 हजार 253 दर्ज की गई है।

न्यू देहली पोस्ट

क्या संभल बनेगा सियासत का नया केंद्र?

राजनीतिक डेस्क

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी को नया हिंदुत्व मुद्दा चाहिए, और संभल का मंदिर विवाद इस राजनीति के केंद्र में आता दिख रहा है। अब सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर भारी पड़ेगा? या फिर यूपी की सत्ता में कोई नया समीकरण देखने को मिलेगा? 2027 के चुनाव तक यह सियासी लड़ाई और तेज होने वाली है!

वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है लेकिन चुनावी मुकाबले की तैयारी अभी से ही देखी जा रही है। सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा पीएडीए की राजनीति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं तो बीजेपी को अपने हिंदुत्व पर गुमान है और बीजेपी उसी हिंदुत्व के जरिये आगे की राजनीति को भी फतह करने को तैयार है। पीएडीए और हिंदुत्व की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है इसके आंकलन भी किये जा रहे हैं। यूपी में भले बीजेपी की सरकार है लेकिन वहां अभी भी ठसक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही चलती है अजर जाहिर है कि योगी अगले चुनाव में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए कई और फ्रंट खोल सकते हैं। अभी संभल का मामला गर्म है और इस गर्मी को बीजेपी वाले और योगी और भी गरमाने को तैयार हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संभल को लेकर बड़ा बयान दिया है, लेकिन इस बार उनका रुख कुछ अलग नजर आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य द्वारा आयोजित महाकुंभ पर महामंथन कार्यक्रम में जब उनसे संभल के मौजूदा विवाद पर सवाल किया गया, तो उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब वेद-पुराण और ऐतिहासिक संदर्भों के जरिए दिया। सिर्फ यही नहीं, सीएम योगी ने इस दौरान दुनिया में भगवा लहराने का भी ऐलान कर दिया। उनका यह बयान साफ इशारा करता है कि 2027 के चुनाव से पहले हिंदुत्व की पिच और मजबूत करने की तैयारी हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या योगी का यह बयान यूपी की राजनीति में कोई नया मोड़ लाएगा?

लगता है संभल के जरिये आगामी राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है और यही कि संभल के इतिहास को नए तरीके से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव की आहट तेज हो गई है, और इस बार सियासत की धुरी बन चुका है संभल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर महामंथन कार्यक्रम में संभल को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने चुनावी राजनीति को और गरमा दिया है। उन्होंने इतिहास और वेद-पुराणों का हवाला देते हुए कहा कि संभल भगवान विष्णु के दसवें अवतार कल्कि का जन्मस्थान है और यह हमेशा से एक तीर्थ स्थल रहा है। साथ ही, उन्होंने 1529 में मीर बाकी द्वारा संभल के हरि मंदिर को गिराए जाने की ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र किया।

संभल का मंदिर-मस्जिद विवाद अब हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनता दिख रहा है। नवंबर 2023 में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़के दंगे भले ही शांत हो गए हों, लेकिन राजनीति अब तक सुलग रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में 68 तीर्थ स्थलों का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक सिर्फ 18 ही खोजे जा सके हैं और 19 कूपों की खुदाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 56 सालों तक यहां शिव मंदिर में जलाभिषेक क्यों नहीं हुआ? इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर पलटवार किया है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि संभल पर कोई कब्जा नहीं हुआ और यहां 30 सालों से कोई दंगा-फसाद नहीं हुआ है।

उधर ,अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए पिछड़ा, दलित, मुस्लिम फॉर्मूला तैयार किया है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा। यूपी में ओबीसी 40%, दलित 21% और मुस्लिम 19% आबादी है। ऐसे में बीजेपी की हिंदुत्व पिच पर समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण बड़ी चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि सीएम योगी हिंदुत्व को चुनावी केंद्र बनाकर जातिगत राजनीति को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भगवा मेरी पहचान है, सनातन धर्म की पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया इसे अपनाएगी।

यूपी बीजेपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर क्यों मची है रार?

न्यूज़ डेस्क

यूपी बीजेपी में ऊपर से देखने में भले ही सब कुछ ठीक लग रहा हो लेकिन भीतर ही भीतर जिला इकाइयों में तूफ़ान आया हुआ है। मामला है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और उसकी टीम की घोषणा। पहले यह मन जा रहा था कि फरवरी के अंत तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अब एक और नयी तारीख सामने आयी है और वह तारीख है 16 मार्च। बता दें कि पार्टी के मंडल अध्यक्षों की घोषणा महीने भर पहले ही कर दी गई थी लेकिन जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर प्रदेश इकाई के पसीने छूट रहे हैं। सामने विधान सभा चुनाव है और सपा से बीजेपी की लड़ाई होनी है। लेकिन जिला अध्यक्षों को लेकर जिस ग्तारह से एक -एक जिले में कई उम्मीदवार खड़े हो गए हैं उससे पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ गई है।

यूपी में जिला और महानगर को जोड़ कर 98 अध्यक्ष होते हैं। इनके नाम तय करने से पहले उस जिले के पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों से चर्चा हुई। इसके बाद हर पद के लिए कुछ नेताओं के नाम का पैनल बना। फिर यूपी बीजेपी कोर कमेटी से इस पर चर्चा हुई। इस कमेटी में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं। फिर आरएसएस के क्षेत्र और प्रांत प्रचारकों से विचार विमर्श हुआ। इसके बाद भी लिस्ट तैयार नहीं हो पाया. कहा गया कि दलित और महिला नेताओं की संख्या कम है। तो मुख्य चुनाव अधिकारी महेन्द्र नाथ पांडे के साथ कई दौर की बैठकें हुई।

गौरतलब है कि जिला अध्यक्ष के लिए एक एक नाम पर विवाद है। इलाके के सांसद अपना आदमी चाहते हैं. तो वहां के प्रभावशाली मंत्री की पसंद कोई और है। संघ किसी और को ये जिम्मेदारी देना चाहता है। विधायकों में भी जिला अध्यक्ष के नाम को लेकर आपस में जबरदस्त खींचतान जारी है। कई मामले तो दिल्ली दरबार तक पहुंच गए। कुछ मामलों में पैसे के बदले पद देने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसी शिकायतें लेकर दो सांसद तो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गए। एक जिले में एक मंत्री के खिलाफ पार्टी के सभी विधायक एकजुट हो गए हैं। मामला आर पार जैसा हो गया है।

यूपी में ठीक दो साल बाद मतलब 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए जिला अध्यक्ष के बहाने ही सब अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हैं। यूपी में बीजेपी की नया प्रदेश अध्यक्ष भी तय होना है। उनकी अगुवाई में विधानसभा का चुनाव होना है।

यूपी में ठीक दो साल बाद मतलब 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए जिला अध्यक्ष के बहाने ही सब अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हैं। यूपी में बीजेपी की नया प्रदेश अध्यक्ष भी तय होना है। उनकी अगुवाई में विधानसभा का चुनाव होना है। नया अध्यक्ष ब्राह्मण होगा या फिर दलित या ओबीसी समाज से. अभी सस्पेंस बना है। इस पद के दावेदार अपने अपने हिसाब से लॉबिंग कर रहे हैं। अगर नया अध्यक्ष पिछड़े समाज का होगा तो फिर किस बिरादरी से ?अभी फैसला होना बाकी है।

क्या उत्तराखंड के रास्ते फिर शुरू होगी मानसरोवर की यात्रा?

न्यूज़ डेस्क

उत्तराखंड के लोगों को अब इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही उनके राज्य से होकर पवित्र मानसरोवर की यात्रा शुरू हो सकती है। लोगों का कहना है कि भारत और चीन के बीच जिस तरह से संबंध सुधरते दिख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि चमोली के माणा और नीति घाटी के रास्ते मानसरोवर की यात्रा शुरू हो सकती है। और ऐसा होता है तो यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इस यात्रा से यहाँ के लोगों को कई तरह के लाभ भी मिल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि इस दिशा में दोनों देश आगे क्या कुछ करते हैं ?

सूबे के पुराने लोग कहते हैं कि 60 के दशक तक चमोली के रास्ते से ही मानसरोवर की यात्रा जाती थी। सब कुछ खुशहाल था लेकिन वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया। 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई और सब कुछ बदल गया। लड़ाई से पहले इसी रास्ते से कई तरह के व्यापार भी होते थे। लड़ाई के बाद व्यापार भी बंद हो गया और मानसरोवर की यात्रा भी रुक गई। बाद के कई वर्षों बाद पिथौरागढ़ होकर मानसरोवर की यात्रा होने लगी। लेकिन कोविड और सीमा पर तनाव की वजह से वह भी बंद हो गया।

बता दें कि माणा को भारत का आखिरी आबाद गांव कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि यह देश का पहला गांव है। धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। यह गांव बदरीनाथ धाम के पास है। बदरीनाथ धाम में माथा टेकने के बाद तीर्थयात्री इधर से मानसरोवर के लिए निकल जाते थे। लोगों को अब उम्मीद है कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव कम हो रहे हैं और कई मसलों पर दोनों देश आपसी समझौता भी कर रहे हैं ऐसे में मानसरोवर की यात्रा को लेकर भी सरकार बात कर सकती है। और ऐसा हुआ तो सूबे के लिए बड़ी बात होगी।

उत्तराखंड में शुरू हुई चार नई हेली सेवाएं

न्यूज़ डेस्क

प्रधानमंत्री मोदी की उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में चार हेली सेवाएं पिछले दिनों शुरू की गई है। इन सेवाओं से नैनीताल ,मसूरी ,बागेश्वरी के साथ ही हल्द्वानी तक हवाई यात्रा अब आसान हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस सेवा से पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को कई तरह के रोजगार भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नई हेली सेवाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'उड़ान' योजना का हिस्सा हैं। इस योजना का मकसद हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच में लाना है। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बागेश्वर, नैनीताल और मसूरी सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन जगहों की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक मंदिर और समृद्ध संस्कृति देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। नई हेली सेवाओं से पर्यटकों के लिए इन स्थलों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल शहर अपनी खूबसूरत झीलों और नयना देवी शक्तिपीठ और कैंची धाम जैसे धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह, बागेश्वर अपने पवित्र बागनाथ मंदिर और उत्तरायणी मेले के लिए जाना जाता है। हेली सेवा शुरू होने से पर्यटक इन क्षेत्रों की सुंदरता और संस्कृति का आनंद आसानी से ले सकेंगे।

देहरादून से इन स्थानों तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में 8 से 10 घंटे लगते थे, लेकिन हेली सेवा के शुरू होने से यह यात्रा अब सिर्फ एक घंटे में पूरी हो जाएगी। यह न सिर्फ समय की बचत करेगा, बल्कि आपात स्थिति में भी लोगों के लिए मददगार साबित होगा। इससे स्थानीय लोगों को चिकित्सा और अन्य जरूरी सेवाएं जल्दी मिल सकेंगी।उत्तराखंड में अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर हेली सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी हैं। राज्य में 18 और हेलीपोर्ट्स का निर्माण कार्य चल रहा है। इनके बनने से प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों को भी हवाई संपर्क मिल जाएगा।

अडानी को लेकर आदित्य ठाकरे को डर क्यों ?

न्यूज़ डेस्क

मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, बल्कि देश की आर्थिक राजधानी है। अगर यह हाथ से गई, तो इसे गुजरात नहीं, बल्कि सीधे अडानी के हवाले कर दिया जाएगा। यह महायुति सरकार मुंबई को बेचने पर तुली है।''

ये शब्द हैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे की। पिछले दिनों मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। उनके बयान से साफ़ झलक रहा था कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार आगामी मनपा चुनाव में बहुत कुछ कर सकती है और जनता को लुभाकर मनपा पर भी कब्जा कर सकती है।

ठाकरे ने कहा कि हमें जात-पात और धर्म से ऊपर उठकर शिवसेना का समर्थन करना होगा और मुंबई को इन गद्दारों के हाथों में जाने से बचाना होगा। आदित्य ठाकरे ने मुंबई के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर मुंबई गद्दारों के हाथ में गई तो वह महाराष्ट्र से बंटेगी ही नहीं, बल्कि कटेगी भी और अडानी के कब्जे में चली जाएगी। उन्होंने शिवसैनिकों से आह्वान करते हुए कहा कि मुंबई को बचाना जरूरी है। यह सिर्फ चुनाव की लड़ाई नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है। मुंबई को मेयर न देकर भाजपा और उसके सहयोगी दल सिर्फ मुंबई को लूटना चाहते हैं। अगर हमने अब नहीं लड़ा, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2014 में भाजपा ने अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, लेकिन 2019 में उन्होंने शिवसेना के साथ किया गया वादा तोड़ दिया। अगर उस वक्त शिवसेना उनके साथ न होती, तो वे तीन सौ सीटें पार नहीं कर सकते थे। ठाकरे ने कहा इस बार भाजपा सत्ता के नशे में थी और संविधान बदलने की योजना बना रही थी। लेकिन 'इंडिया' गठबंधन ने उन्हें

रोक दिया और उनकी सीटों को 240 पर अटका दिया। शिवसेना ने विधान परिषद और सिनेट चुनावों में जीत दर्ज की और हम मनपा चुनाव में भी जीत दर्ज करेंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद कर दिया है। मुंबई की आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है। बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर गुजरात भेजे जा रहे हैं। ऊपर बैठे लोग सिर्फ गुजरात की चिंता कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई में सड़कें खोदी गई हैं, जगह-जगह गड्ढे हैं। 2022 में मुंबई में 6000 करोड़ रुपए के रोड टेंडर निकाले गए थे। लेकिन अब तक सिर्फ 26 प्रतिशत काम हुआ है। मनपा के अस्पताल, जो कभी कोविड के दौरान डब्ल्यूएचओ द्वारा सराहे गए थे, अब दयनीय स्थिति में हैं। दवाइयां नहीं हैं, एक्सरे मशीनें नहीं हैं।

साउथ के जननायक बनने की तैयारी में हैं अभिनेता विजय

न्यूज़ डेस्क

देश की राजनीति से लेकर सामाजिक परिवर्तन में युवाओं की भूमिका को भला कौन नकार सकता है ? आजादी की लड़ाई में भी देश के युवाओं ने ही गांधी जी का साथ दिया था।खून बहाये थे ,फांसी पर चढ़े थे और कुर्बानी देकर ही देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई थीदेश के युवाओं ने। ये देश के केवल युवा ही थे। ये हिन्दू -मुसलमान नहीं थे ,सिर्फ युवा थे जो भारत माता की लड़ाई लड़ते रहे। समय बदला। राजनीति भी बदली। बदलती राजनीति में भी देश के युवाओं ने बहुत कुछ किया है। जिन युवाओं ने राजनीति के जरिए देश में परिवर्तन लाने की कोशिश की ,उसमे भी वे सफल रहे। जहाँ भी युवाओं को मौक़ा मिला अपने हिसाब से बहुत कुछ किया और आगे का काम अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया। अब इसी तरह की एक युवा शक्ति राजनीति दक्षिण भारत के तमिलनाडु में उठती दिख रही है। इस युवा राजनीति को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं दक्षिण के सुपर स्टार से राजनीति में प्रवेश कर रहे अभिनेता विजय। उनकी अदा पर तो दक्षिण भारत मर मिटने को तैयार है ही उत्तर भारत में भी अभिनेता विजय की खूब चर्चा हो रही है। दक्षिण के राज्यों में तो उनकी राजनीति लोगों और समाज को खूब भा रही है। तमिलनाडु के अगले चुनाव में अभिनेता विजय का लिटमस टेस्ट होना है। वे क्या कुछ कर पाते हैं इसका टेस्ट भी होना है लेकिन एक बात तो तय है कि विजय जिस तरह की आपसी सौहार्द्य की राजनीति को आगे बढ़ते दिख रहे हैं उससे कई दलों की नींद् उड़ती जा रही है। पिछले दिनों तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम टीवीके पार्टी के प्रमुख विजय ने भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। यह पार्टी चर्चा में है। चेन्नई के रोयापेट्टा स्थित वाईएमसीए मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में 15 मस्जिदों के इमामों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विजय को सफेद कपड़ों में इफ्तार में शामिल होते और नमाज अदा करते देखा गया।

असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने इस्लामिक परंपराओं का पालन करते हुए पूरे दिन का रोजा रखा और शाम को नमाज अदा करने के बाद इफ्तार किया। उनके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जिनमें अभिनेता को आमंत्रित लोगों के साथ दुआ करते हुए देखा गया। इस आयोजन में लगभग 3,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। विजय के इस कदम को उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 2024 में टीवीके पार्टी की स्थापना के बाद से उन्होंने भ्रष्टाचार और विभाजन के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी दल का समर्थन नहीं किया। इससे पहले 2021 के तमिलनाडु स्थानीय निकाय चुनावों में उनके फैन क्लब ने 169 में से 115 सीटें जीतकर विजय की राजनीतिक साख मजबूत कर दी थी।

विनेश ने संजय सिंह को क्यों कहा डमी बृजभूषण?

न्यूज़ डेस्क

पिछले दिनों खेल मंत्रालय द्वारा कुश्ती निकाय के निलंबन को रद्द करने पर पहलवान से नेता बनी विनेश फोगट ने निराशा जताते हुए कहा कि "मैं यहां गर्व और दुख दोनों के साथ खड़ी हूं। कई विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने खेलों के लिए बहुत कुछ किया है।" हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक ने हरियाणा विधानसभा में बृजभूषण का नाम लिए बिना कहा, "मैं दुख के साथ कह रही हूं कि दो साल तक हम सड़कों पर संघर्ष करते रहे... हम कुश्ती के खेल को बचाने के लिए लड़ रहे थे। और अब दो दिन पहले आपकी पार्टी (भाजपा) ने खेल को फिर से उनके हाथों में दे दिया है।"बता दें कि पहलवान से नेता बनी विनेश फोगट ने 2023 में पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था।

गौरतलब है कि फोगाट राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग ले रही थीं। बाद में उन्होंने विधानसभा परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि डब्ल्यूएफआई प्रमुख संजय सिंह एक "डमी" हैं और बृजभूषण अभी भी शो चला रहे हैं। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का निलंबन हटा दिया है, जिससे खेल को लेकर महीनों से चली आ रही

अनिश्चितता समाप्त हो गई है और गतिविधियों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।मंत्रालय ने प्रशासन और प्रक्रियात्मक अखंडता में खामियों के कारण 24 दिसंबर, 2023 को डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया। ओलंपियन फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने बृज भूषण पर जूनियर पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था और जंतर-मंतर पर लंबा विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और पूर्व भाजपा सांसद इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। बृजभूषण ने आरोपों से इनकार किया है। इससे पहले, जब फोगाट सदन में इस मुद्दे पर बोल रही थीं, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, "हमारे मन में आपके लिए इतना सम्मान इसलिए नहीं है कि आप किसी राजनीतिक दल की नेता हैं, बल्कि इसलिए है कि आप एक खिलाड़ी के तौर पर देश का गौरव हैं... इसका मतलब यह नहीं है कि हम इन बातों को इस तरह से पेश करें।"

मंत्री को जवाब देते हुए फोगाट ने कहा, "हमारा संघर्ष, यह लड़ाई (पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ) किसी विशेष पार्टी के कारण शुरू नहीं हुई थी... हमने खिलाड़ी के तौर पर अपनी आवाज उठाई थी और एक खिलाड़ी हमेशा एक खिलाड़ी ही रहेगा।"

उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनके उस वादे की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने उन्हें पदक विजेता की तरह सम्मानित करने का वादा किया था, जब 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले अधिक वजन होने के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने कहा था कि विनेश हमारी बेटी है और उसे ओलंपिक रजत पदक विजेता के समान ही पुरस्कार दिया जाएगा... यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।"

न्यू देहली पोस्ट

क्या अब आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे दोषी करार नेता?

राजनीतिक डेस्क

क्या दोषी करार नेता अब आजीवन चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे ? ये बातें इसलिए कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इनदिनों एक ऐसी याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमे जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत दोषियों को चुनाव लड़ने से छह साल की अयोग्यता की बजाए आजीवन प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई है। हालांकि इस याचिका पर अभी सुनवाई ही चल रही है लेकिन कोर्ट के रुख को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला कर सकती है। और ऐसा हुआ तो देश के कई नामी नेताओं की राजनीति ख़त्म हो सकती है।

पिछले सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन पिछले मामलों का विवरण देने को कहा था, जिनमें आयोग ने दोषियों की अयोग्यता अवधि को कम करने के लिए आरपी अधिनियम के तहत अपने विवेक का इस्तेमाल किया था। बता दें कि जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 कुछ मामलों में दोषियों को छह साल के लिए अयोग्य ठहराने का आदेश देती है, जिसमें किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना और दो या अधिक साल की जेल की सजा के मामले शामिल हैं।जबकि इन अपराधों के लिए अयोग्यता स्वचालित है। धारा 10 ए के तहत, चुनाव आयोग के पास तीन साल के लिए चुनाव खर्च का हिसाब न देने वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने का अधिकार है। आरपी अधिनियम के तहत, चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धारित तरीके से चुनाव आयोग को चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है।

चुनाव आयोग को आरपी अधिनियम की धारा 8ए के अनुसार भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्य ठहराए गए लोगों को छोड़कर, अयोग्य ठहराए गए लोगों को राहत देने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 11 चुनाव आयोग को अयोग्य ठहराए जाने की अवधि को हटाने या कम करने का अधिकार देती है।धारा 11 में कहा गया है, "चुनाव आयोग, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इस अध्याय 1 [(धारा 8ए के तहत छोड़कर)] के तहत किसी भी अयोग्यता को हटा सकता है या किसी भी ऐसी अयोग्यता की अवधि को कम कर सकता है।"

बता दें कि अयोग्य उम्मीदवार चुनाव आयोग में अपील कर सकते हैं। इसके बाद निर्वाचन निकाय सुनवाई करता है और अपने निर्णय के लिए कारण बताते हुए आदेश पारित करता है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने द्वारा आदेशित ऐसी कटौती या निष्कासन की सूची सार्वजनिक रूप से नहीं रखी है। हालाँकि, यह अयोग्य व्यक्तियों की राज्यवार वार्षिक सूची प्रकाशित करता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अयोग्यता के संबंध में हाल के दिनों में इसके द्वारा जारी किए गए आदेश भी शामिल हैं।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सबसे हालिया आदेश अक्टूबर 2022 का है, जब आयोग ने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में चामराजपेट निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार संपांगी राज की अयोग्यता को लगभग दो साल तक कम कर दिया था। चुनाव खर्च का हिसाब न देने के कारण राज को अगस्त 2021 में चुनाव आयोग ने तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्होंने तीन साल की अयोग्यता के खिलाफ अपील की और अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग के आदेश के समय तक इसे कम कर दिया गया। मार्च 2021 में, चुनाव आयोग ने 2019 में पुडुचेरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार एस भास्करन के लिए तीन साल की अयोग्यता को कम कर दिया, क्योंकि उन्होंने कानून द्वारा अपेक्षित तरीके से चुनाव खर्च का लेखा-जोखा दर्ज नहीं किया था।

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अयोग्यता अवधि भी 2016 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कम कर दी गई थी। यह मामला सिक्किम के पशुपालन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गायों की खरीद के लिए निर्धारित धन के दुरुपयोग से संबंधित था। चुनाव आयोग को दी गई अपनी अपील में तमांग ने कहा कि उन्होंने 2017 से 2018 तक अपनी पूरी सजा काट ली है। तमांग की छह साल की अयोग्यता को घटाकर एक साल और एक महीना कर दिया गया। वह 2019 सिक्किम विधानसभा चुनाव लड़ने में असमर्थ थे क्योंकि उस समय उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन चुनाव आयोग के आदेश के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा और उसी वर्ष विधानसभा के लिए चुने गए।

महाराष्ट्र में सरकार बदलती गई नहीं रुकी किसानों की आत्महत्या

न्यूज़ डेस्क

पिछले दिनों महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव ने सदन में कहा कि जो वे कह रहे हैं वह भले ही आंशिक रूस से ही सच हो लेकिन राज्य में पिछले 56 महीनो में औसतन प्रति दिन आठ किसानों ने आत्महत्या की है। वे विधान परिषद में बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एनसीपी एमएलसी शिवाजीराव गरजे द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।जाधव ने यह भी कहा कि छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती संभागों में किसानों की आत्महत्या की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। हालांकि मंत्री ने किसानों की आत्महत्या में योगदान देने वाले कारकों और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित किया लेकिन जो आंकड़े उन्होंने दिए उससे महाराष्ट्र की राजनीति और भी गर्म हो गई। बता दें कि पिछले चुनाव के दौरान भी किसानो की आत्महत्या को लेकर खूब राजनीति हुई थी और लगभग सभी पार्टियां इस मुद्दे को उठा भी रही थी। पार्टियां लोगों के सामने यही कह रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्रदेश में अब किसी भी किसान के सामने कोई संकट नहीं आएगा जिससे कि उन्हें अपनी जान गवानी पड़े।

लेकिन चाहे पिछली शिंदे की सरकार रही हो या फिर अभी फडणवीस की सरकार चल रही हो ,किसानो के हालात नहीं बदले। उनकी आत्महत्या की सूची कम नहीं हुई। याद रहे शिंदे की सरकार भी बीजेपी की अगुवाई में ही चल रही थी और अब फडणवीस की सरकार की अगुवाई भी बीजेपी ही कर रही है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं इसपर आज तक किसी भी सरकार ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है। मंत्री मकरंद जाधव ने जो आंकड़े सदन में रखे हैं वे चौंकाते हैं और दुखी भी करते हैं। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष मराठवाड़ा संभाग में 952 किसानों ने आत्महत्या की जबकि अकोला में 168, वर्धा में 112, बीड में 205 और अमरावती संभाग में 1,069 किसानों ने आत्महत्या की है। जानकारी के मुताबिक़ जैसा की मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2024 के बीच छत्रपति संभाजीनगर संभाग में 952 किसानों ने आत्महत्या की।उनमें से 707 सहायता के पात्र थे और 433 मामलों में सहायता प्राप्त हुई।

बीड जिले में, 167 मामलों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई और 108 मामलों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।अमरावती संभाग में, 441 मामले सहायता के पात्र थे और 332 को सहायता मिली। एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि जालना जिले के मंथा तालुका में अप्रैल 2023 और सितंबर 2024 के बीच 13 किसानों ने आत्महत्या की।लेकिन मंत्री ने यह भी कहा, "सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उधर एनसीपी (सपा) अध्यक्ष शरद पवार ने किसानों की हालत पर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या लगातार जारी है और दूसरी तरफ सरकार जो कहती है उसे पूरा करती नहीं। पवार ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते रहे हैं। लेकिन किसानों की हालत सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन पर कटाक्ष करते हुए पवार ने दावा किया कि भाजपा शासन में किसानों की आत्महत्याओं की संख्या दोगुनी हो गई है।

पवार ने दावा किया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और वे कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय किसानों की आत्महत्या दोगुनी हो गई हैं।" एनसीपी (सपा) प्रमुख ने कहा कि समय की मांग है कि राज्य में सरकार बदली जाए और ऐसी सरकार बनाई जाए जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करे। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, "केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों की मुश्किलें कम करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। आप नौकरियों की कमी के कारण युवाओं को संकट में देखेंगे। हमें सरकार बदलनी होगी।"

सर्वे में नीतीश का इक़बाल कमजोर तेजस्वी सीएम के पसंदीदा उम्मीदवार

राजनीतिक डेस्क

ऐसा पहली बात हुआ कि सत्ता में बैठे कोई ताकतवर नेता का इक़बाल अचनाक नीचे गिर गया है। आज तक ऐसा नहीं देखा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि 20 सालों से सत्ता की कुर्सी पर बैठे किसी बड़े नेता और मुख्यमंत्री को बिहार की जनता अचानक नापसंद कर दे। क्या कोई प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी ऐसी ही राय रख सकता है ? लेकिन बिहार में चुनाव से पहले जो सर्वे सामने आया हैं वह तो यही कह रहा है कि बिहार में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। सब कुछ बदलने को तैयार है और सबसे बड़ी बात कि इस बार राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखने को बेकरार है। जिस राजद प्रमुख लालू यादव को आज भी बीजेपी और जदयू के लोग चारा चोर कहने से नहीं चूक रहे हैं और बिहार की बर्बादी का सबसे बड़े कारण मानते हैं अब उसी राजद प्रमुख लालू यदव के पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार की जनता सत्ता की चाभी देने को तैयार है। सी वोटर का यह सर्वे कितना सच होगा और फिर चुनाव नजदीक एते ही इसमें कितना फेर बदल होगा यह तो बाद की बात है लेकिन अभी तो सर्वे यही बता रहा है कि नीतीश कुमार का इक़बाल ख़त्म हो गया है। उनके चाहने वाले लोगों की संख्या जहाँ 18 फीसदी पर सिमट गई है वही तेजस्वी यादव को 41 फीसदी लोग सीएम के रूप में देखना चाहते है।

यह सर्वे भले ही राजद के लिए उत्साहवर्धक हो सकता है लेकीन जदयू और बीजेपी के लिए किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं। बिहार में सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा 41 फीसदी लोग राजद के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में बड़ी कमी आई है और सिर्फ 18 फीसदी लोगों की पसंद वे हैं। उसके बाद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 15 फीसदी लोगों ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। भाजपा के सम्राट चौधरी को आठ फीसदी और लोजपा के चिराग पासवान को चार फीसदी लोगों ने पसंद किया है। इस सर्वे में दूसरी अहम बात यह है कि बिहार के 50 फीसदी लोगों ने कहा है कि वे एनडीए सरकार से नाखुश हैं और इसे बदलना चाहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार के कमजोर होने पर नेतृत्व के नाते पहली पसंद तेजस्वी यादव होंगे क्योंकि पिछले 11 साल में उनका नेतृत्व बिहार में स्थापित हुआ है। वे लालू प्रसाद और नीतीश की विरासत, सामाजिक समीकरण और वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके मुकाबले भाजपा ने अपना कोई नेता अभी तक स्थापित नहीं किया है। तेजस्वी पिछले 10 साल में साढ़े तीन साल उप मुख्यमंत्री रहे और करीब सात साल नेता प्रतिपक्ष रहे। उनके अलावा दूसरा कोई नेता इतने लंबे समय तक नेतृत्व की पोजिशन में नहीं रहा है।

आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की अनूठी योजना शुरू

न्यूज़ डेस्क

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की भी घोषणा की। पहले यह सुविधा केवल दो बच्चों तक सीमित थी, लेकिन अब यह सभी बच्चों के लिए लागू होगी।

जहाँ एक तरफ उत्तर भारतीय राज्यों में बढ़ती जनसँख्या बड़ी समस्या बनी हुई है वही दक्षिण के राज्य की आंध्र प्रदेश सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनूठी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत तीसरा बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को 50,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही, यदि महिला लड़के को जन्म देती है तो उसे एक गाय भी उपहार में दी जाएगी। यह घोषणा राज्य के विजयनगरम से तेलुगू देशम पार्टी के सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने की।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश में घटती जनसंख्या दर को संतुलित करना और जनसांख्यिकीय असंतुलन को नियंत्रित करना है। राज्य सरकार ने महसूस किया है कि दक्षिण भारत में जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है, जो भविष्य में जनसंख्या संतुलन पर असर डाल सकती है। सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत दी जाने वाली नकद प्रोत्साहन राशि का भुगतान वे अपने वेतन से करेंगे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पहले वे परिवार नियोजन के समर्थक थे, लेकिन अब वे अपनी राय बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए लॉन्ग टर्म जनसंख्या मैनेजमेंट की आवश्यकता है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "यदि हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का सही ढंग से प्रबंधन कर सके, तो भारत और भारतीय नागरिक भविष्य में और भी मजबूत बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की भी घोषणा की। पहले यह सुविधा केवल दो बच्चों तक सीमित थी, लेकिन अब यह सभी बच्चों के लिए लागू होगी।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। तीसरा बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को 50,000 रुपये की नकद राशि दी जाएगी। यदि महिला लड़के को जन्म देती है तो उसे एक गाय भी भेंट की जाएगी। सभी महिला कर्मचारियों को अब प्रसव के समय मातृत्व अवकाश मिलेगा, चाहे उनके कितने भी बच्चे हों। इस योजना का उद्देश्य राज्य में जनसंख्या असंतुलन को दूर करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और लॉन्ग टर्म जनसंख्या मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना है। आंध्र प्रदेश सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य को भविष्य में जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी।

आखिर स्टालिन ने क्यों बुलाई विपक्ष की बैठक ?

न्यूज़ डेस्क

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन परिसीमन और त्रिभाषा फॉर्मूले के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी बनाई है, जिसकी पहली बैठक 22 मार्च को होगी। स्टालिन ने इस बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। स्टालिन ने अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं से 22 मार्च को होने वाली जेएसी की पहली बैठक में अपने प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया है, ताकि परिसीमन मुद्दे पर साझा रणनीति बनाई जा सके।

गौरतलब है कि परिसीमन और त्रिभाषा नीति के खिलाफ स्टालिन ने पांच मार्च को तमिलनाडु की सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक की थी। भाजपा और एकाध अन्य पार्टियों को छोड़ कर बाकी पार्टियां इसमें शामिल हुई थीं। बैठक में इन मुद्दों पर जॉइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी बनाने का फैसला हुआ था। बताया गया है कि परिसीमन में राज्यों का प्रतिनिधित्व बचाने और प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी हो, इसके लिए जेएसी काम करेगी।

मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं को लिखी चिट्ठी में स्टालिन ने चेतावनी दी है कि परिसीमन से तमिलनाडु जैसे कम जनसंख्या वाले राज्यों पर असर पड़ेगा। उन्होंने लिखा है कि देश में 1952, 1963 और 1973 में परिसीमन हुआ था। 1976 में परिसीमन को साल 2000 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक रोक दिया गया। वहीं, 2002 में परिसीमन पर 2026 तक रोक बढ़ा दी गई थी। उन्होंने लिखा है कि 2021 की जनगणना में देरी के वजह से परिसीमन तय समय से पहले हो सकता है। इससे अपनी जनसंख्या नियंत्रित रखने वाले राज्य प्रभावित हो सकते हैं।

स्टालिन ने दक्षिण भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा और उत्तर में पंजाब से जेएसी में शामिल होने के लिए उनकी औपचारिक सहमति मांगी है। गौरतलब है कि ओडिशा में भाजपा की सरकार है। इसलिए स्टालिन की बुलाई बैठक में ओडिशा का कोई प्रतिनिधि शायद ही शामिल हो। बहरहाल, सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा था कि अगर संसद में सीटें बढ़ती है तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा था कि 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों के सीमा तय करते समय 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए।

क्या नयी शिक्षा नीति 'विनाशकारी नागपुर योजना' है?

न्यूज़ डेस्क

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को "विनाशकारी नागपुर योजना" करार दिया और दोहराया कि राज्य इसे स्वीकार नहीं करेगा, भले ही केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपये प्रदान करे। स्टालिन ने आगे यह भी कहा कि ''आपने टेलीविजन पर संसदीय कार्यवाही देखी होगी। वह अहंकार से बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु को 2,000 करोड़ रुपये तभी दिए जाएंगे, जब हिंदी और संस्कृत को स्वीकार किया जाएगा। कौन? यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे।" बता दें कि तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहा है। तमिलनाडु के सीएम का मानना है कि यह तमिलनाडु में शिक्षा के विकास को पूरी तरह से नष्ट कर देगा।उन्होंने आरोप लगाया, "एनईपी छात्रों को शिक्षा में लाने की कोशिश करने के बजाय, छात्रों को शिक्षा से दूर करने के लिए सभी कार्य योजना बनाती है।"

मुख्यमंत्री स्टालिन ने आरोप लगाया कि शिक्षा में सांप्रदायिकता का प्रवेश,किया गया है और शिक्षा का निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिससे केवल अमीर लोग ही शिक्षा पा सकते हैं। छोटे बच्चों पर भी इसका असर पड़ना है। इस नीति से कई तरह की पढ़ाई प्रभावित होगी।

यही वजह है कि तमिलनाडु ने इस शिक्षा नीति का विरोध करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एनईपी को स्वीकार नहीं करेगा।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम आपकी विनाशकारी नागपुर योजना को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही आप 10,000 करोड़ रुपये (राज्य के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये से अधिक) प्रदान क्यों न करें। बता दें कि 10 मार्च को, तमिलनाडु के सांसदों ने प्रधान को संसद में आधे घंटे के भीतर अपने आपत्तिजनक शब्द वापस लेने पर मजबूर कर दिया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि वे डीएमके नेता दिवंगत कलैगनार एम करुणानिधि के उत्तराधिकारी हैं।"

"उन्होंने साबित कर दिया है कि वे तमिलनाडु के अधिकारों के लिए निडरता से लड़ेंगे, जबकि एआईएडीएमके के सदस्य भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हैं।" मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद में डीएमके सांसदों की लड़ाई उन लोगों के लिए सही जवाब है जो जानना चाहते थे कि राज्य के 39 सांसद क्या करेंगे। "हम उसी लड़ाई की भावना के साथ तमिलनाडु के लिए लड़ेंगे। हम लोगों की सरकार (तमिलनाडु सरकार) को उसी जिम्मेदारी की भावना के साथ चलाएंगे और इसके लिए आपका समर्थन हमेशा जारी रहना चाहिए।"

तिल वात ,पित्त और कफ निवारण में रामबाण है

हेल्थ डेस्क

आयुर्वेद के अनुसार, तिल का तेल वात, पित्त और कफ को संतुलित करने का कार्य करता है और शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत करता है। तिल के तेल का वर्णन आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथों में जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में किया गया है, जहां इसे स्वास्थ्य लाभ के लिए एक प्रमुख औषधि माना गया है। यह त्वचा को कोमल और चमकदार बनाने में मदद करता है। साथ ही, तिल के तेल का सेवन करने से यह शरीर के भीतर सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। यह शरीर के जोड़ों में लचीलापन बनाए रखने में भी सहायक है। तिल के तेल में एक विशेष एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो तेल को गर्मी और समय के साथ खराब होने से बचाता है।

हमारे शरीर के लिए तिल जितना फायदेमंद हैं, तिल का तेल उससे ज्यादा फायदेमंद है। तिल का तेल एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जिसे सदियों से भारतीय घरों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह तेल न केवल स्वाद में बेमिसाल है, बल्कि इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण भी यह एक अमूल्य रत्न माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में तिल का तेल विशेष रूप से सर्दियों में आयुर्वेदिक उपचारों में एक अहम स्थान रखता है।

तिल के तेल के फायदेमंद

प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका उपयोग बाहरी और आंतरिक दोनों तरीकों से किया जाता था। इस तेल का इस्तेमाल न केवल खाने में, बल्कि शरीर की मालिश, बालों की देखभाल और त्वचा के लिए भी किया जाता था। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक तिल के तेल को शरीर को अंदर से पोषित करने वाला और बीमारियों से लड़ने में सहायक मानते थे। चरक संहिता में इसे 'बलवर्धक' और 'तन-मन की शांति' देने वाला बताया गया है। इसके अलावा, सुश्रुत संहिता में इसका उपयोग जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों के इलाज के लिए भी किया गया था। यह न केवल आयुर्वेद में बल्कि विज्ञान में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

वैज्ञानिक शोधों से यह साबित हुआ है कि तिल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन 'ई', सेसमिन, सेसमोल और ओमेगा-3 जैसे तत्व होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और दिल को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। यह खालिस देसी तरीका है अपने चेहरे को दमकाने और झुर्रियों को उम्र से पहले न हावी होने देने का. सेसमिन और सेसमोल जैसे तत्व मस्तिष्क में सेरोटोनिन की वृद्धि करते हैं, जिससे तनाव और अवसाद कम होता है। इसके सेवन से मानसिक स्थिति में सुधार होता है और व्यक्ति खुद को ज्यादा शांत और खुश महसूस करता है। साथ ही, तिल का तेल पाचन प्रक्रिया को भी बेहतर बनाता है, जिससे शरीर को उचित पोषण मिल पाता है।

इन बीमारियों में भी है लाभदायक

उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव करने में भी तिल के तेल का कोई जवाब नहीं। तिल में पाया जाने वाला सेसमीन नामक एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। आधुनिक शोधों ने यह भी साबित किया है कि तिल के तेल के सेवन से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही, यह तेल हृदय की सेहत को बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं, जो दिल की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और रक्त प्रवाह को सामान्य रखते हैं। तिल के तेल का एक अन्य लाभ यह है कि यह कब्ज को दूर कर पेट को साफ रखता है।

रमजान में सेहत का ऐसे रखें ख्याल

हेल्थ डेस्क

रमजान का पाक महीना आत्मसंयम, इबादत और रोज़ों का समय होता है। इस दौरान लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते-पीते, जिससे शरीर को कई बदलावों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में सेहतमंद रहना जरूरी है ताकि रोजे अच्छे से रखे जा सकें और किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या न हो। यहां कुछ जरूरी टिप्स दिए जा रहे हैं, जो रमजान के दौरान आपकी सेहत का ध्यान रखने में मदद करेंगे। रोजे के दौरान शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए सहरी और इफ्तार के दौरान भरपूर पानी पिएं। दिनभर पानी न पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि सहरी और इफ्तार के बीच कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं।

सहरी में सही आहार जरुरी

सहरी का भोजन संतुलित और पोषणयुक्त होना चाहिए. हल्का लेकिन ऊर्जा देने वाला आहार लें, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में हों। ओट्स, ब्राउन ब्रेड, अंडे, फल और ड्राई फ्रूट्स अच्छे विकल्प हो सकते हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा नमक या तले-भुने खाने से बचें, क्योंकि इससे दिनभर प्यास ज्यादा लगेगी। दिनभर भूखे रहने के बाद कई लोग इफ्तार में जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे पेट भारी हो जाता है और आलस्य महसूस होता है। इफ्तार खजूर और पानी से शुरू करें, फिर हल्का और पौष्टिक भोजन लें। तली-भुनी चीज़ों से परहेज करें और फाइबर युक्त चीजें ज्यादा खाएं। रमजान में शारीरिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद न करें. हल्की वॉक, योग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। व्यायाम के लिए इफ्तार के बाद का समय सबसे सही होता है, क्योंकि इस समय शरीर में पर्याप्त ऊर्जा रहती है।

पूरी नींद जरुरी

रोजो के दौरान नींद की कमी से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए रात में अच्छी नींद लें और दिन में अगर संभव हो तो हल्की झपकी भी ले सकते हैं. इससे शरीर ऊर्जावान बना रहेगा। रमजान के दौरान चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें। इनमें मौजूद कैफीन डिहाइड्रेशन बढ़ा सकता है और नींद को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही रमजान में मीठे और ज्यादा नमक वाले खाने से बचें। ज्यादा मीठा खाने से अचानक एनर्जी बढ़ती है और फिर तेजी से गिरती है, जिससे सुस्ती आ सकती है। इसी तरह, ज्यादा नमक लेने से प्यास अधिक लगती है और शरीर में पानी की कमी हो सकती है। रमजान के दौरान सेहत का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इबादत। सही खानपान, पर्याप्त पानी, हल्का व्यायाम और पूरी नींद से आप पूरे महीने ऊर्जावान और स्वस्थ रह सकते हैं।

भारत में तेजी से बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के प्रति डब्ल्यूएचओ ने किया आगाह

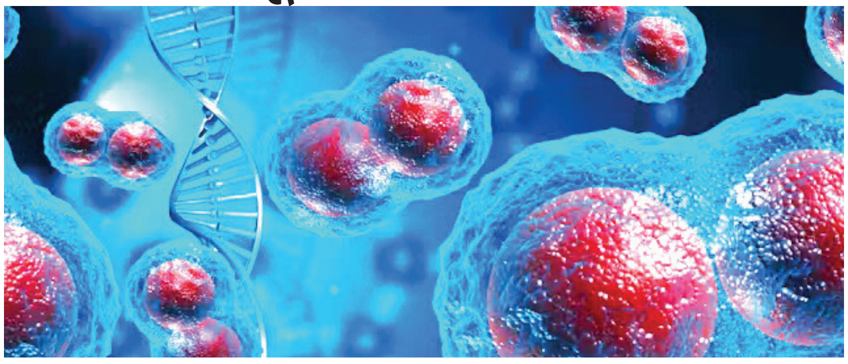

हेल्थ डेस्क

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में सचेत किया है कि दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये पुरे विश्व भर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसी के साथ भारत में भी यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की हालिया रिपोर्टों ने भारत में स्तन कैंसर के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। यह लेख इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

सब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान दर जारी रहती है, तो 2050 तक हर साल 3.2 मिलियन नए मामले और 1.1 मिलियन मौतें होने का अनुमान है।जिन देशों का मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई कम है, वहां वृद्धि दर सबसे अधिक है। कैंसर के मामलों में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है।विश्व में कैंसर से होने वाली 10% से अधिक मौतें भारत में होती हैं, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।भारत में हर तीन में से दो कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है, और महिलाओं पर इसका बोझ पुरुषों की तुलना में अधिक है। आने वाले दो दशकों में, जनसंख्या की उम्र बढ़ने के कारण भारत में कैंसर के मामलों में सालाना 2% की वृद्धि होने का अनुमान है।

युवा महिलाओं में बढ़ता खतरा

भारत में युवा महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है।5-10% मामले आनुवंशिक होते हैं, जबकि 90% जीवनशैली और पर्यावरण से संबंधित होते हैं।पहले से बेहतर पहचान सुविधाओं का न होना और जागरूकता नहीं होने के कारण भी मामलों में वृद्धि हुई है। देर से विवाह, देर से बच्चे पैदा करना, कम स्तनपान और मोटापा भी इसके कारण हो सकते हैं। दूषित डेयरी उत्पाद और कीटनाशक संदूषण जैसे अज्ञात कारक भी स्तन कैंसर का कारण बन सकते हैं। भारत में स्तन कैंसर पश्चिमी देशों की तुलना में एक दशक पहले होता है।यहां स्तन कैंसर 40 की शुरुआत में चरम पर होता है, जबकि पश्चिम में यह 50 के अंत में होता है।यहां का कैंसर अधिक आक्रामक होता है, जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव स्तन कैंसर।

लक्षण और पहचान

स्तन में गांठ, आकार या आकार में परिवर्तन, त्वचा में बदलाव, निप्पल में बदलाव, और बगल में सूजन जैसे लक्षण स्तन कैंसर के संकेत हो सकते हैं।भारत में युवा महिलाओं की बड़ी आबादी के कारण भी मामले बढ़ रहे हैं।जागरूकता और नियमित जांच से शुरुआती पहचान संभव है, जिससे उपचार के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।भारत में जनसंख्या-आधारित स्क्रीनिंग की कमी के कारण, कैंसर का पता देर से चलता है, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। शुरुआती पहचान और जागरूकता ही इसका समाधान है।लोगों को लक्षणों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।नियमित जांच और स्क्रीनिंग से शुरुआती पहचान में मदद मिल सकती है।शुरुआती पहचान से उपचार के बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

मछली पालन के लिए मजबूत तालाब से होगी बेहतर कमाई

कृषि डेस्क

मछली पालन आज की तारीख में अच्छी कमाई का स्रोत है। जिन किसानो के पास थोड़ी सी भी जमीन है ,वे मछली पालन करके अच्छी कमाई कर सकते हैं और अपने परिवार का पालन भी कर सकते हैं। आजकल हर गांव और देहात में बड़े स्तर पर म,मछली पालन के प्रति लोगों की जिज्ञासा जगी है और किसान इससे बेहतर कमाई भी कर रहे हैं। यह कमाई सालों भरने चलने वाला है। सरकार भी मछली पालन के लिए किसानों को कई तरह से मदद कर रही है। मकसद यही है कि हर किसान बेहतर आमदनी करे और अपने परिवार का पालन करे। लेकिन मछली पालन के लिए सबसे जरुरी है एक बेहतर तालाब की। अगर तालाब ठीक नहीं है तो उम्मीद से ज्यादा पछली का उत्पादन नहीं हो सकता। ऐसे में किसानो को सबसे ज्यादा जोर तालाब की बनावट ,उसकी गहराई और लम्बाई ,चौड़ाई पर ध्यान देने की जरुरत है। आज हम मछली पालन के लिए तालाब के बारे में ज्यादा जानकारी देने जा रहे हैं।

मछली पालन के तालाब का चयन सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह मछली फार्म की सफलता को निर्धारित करता है। देश की बढ़ती हुई जनसँख्या को ध्यान में रखते हुए तथा खाने की मांग की पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो गया है की जल संसाधनों का उपयोग अतिरिक्त आहार उत्पादन के लिए किया जाए तथा इन खाद्य पदार्थों को उन स्थानों पर भेजा जाए जहां पर ये मुख्य रूप से खाने के काम लाये जाते है। मत्स्य पालन द्वारा ग्रामीण वर्ग अपनी आर्थिक तथा सामाजिक दशा को सुधार सकता है तथा बेरोजगारी की समस्या को भी समाप्त कर सकता है। आज के तकनिकी युग में ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन तथा समेकित मत्स्य पालन जैसे मछली के साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, पशु पालन इत्यादि के व्यवसाय के एकीकरण से ग्रामीण जनसमुदायों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सकेगा।

भूमि का चयन

तालाब की भूमि का चयन सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो मछली फार्म की सफलता को निर्धारित करता है। तालाब के निर्माण से पहले मिट्टी की जल को धारण करने की क्षमता और मिट्टी की उर्वरता का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यह कारक खेत के तालाब में जैविक और अकार्बनिक निषेचन की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। चयनित स्थल में तालाब को भरने और अन्य उपयोगों के लिए वर्ष भर पर्याप्त जलापूर्ति होना आवश्यक है। तालाब का निर्माण स्थलाकृतिक क्षेत्र पर आधारित होना चाहिए तथा निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए -जमीन ऊसर ना हो तथा बालू, कंकड़ एवं पत्थर युक्त ना हो।दलदली क्षेत्रों में, पसंदीदा आकार के तालाब के बांध बंदी निर्माण के लिए मिट्टी का अधिक संचय करना चाहिए।उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए स्व-जल निकासी वाले तालाब आदर्श होते हैं।मिटटी न ज्यादा अम्लीय हो न ज्यादा क्षारीय हो।आसानी से मछली को बाजार तक पहुंचने के लिए सड़क वा परिवहन का होना आवश्यक।फ्रीड, बीज, उर्वरक और निर्माण सामग्री जैसे इनपुट की व्यस्था भूमि के पास उपलब्ध होनी चाहिए।और भूमि प्रदूषण, औद्योगिक कचरे, घरेलू कचरे और किसी भी अन्य हानिकारक गतिविधियों से मुक्त होनी चाहिए।इसके साथ ही मिटटी में जल धारण क्षमता अधिक हो।मिटटी उर्वर हो, जिससे प्राकर्तिक भोजन की उपलब्धता रहे।

तालाब के मिटटी की पहचान

नए तालाब निर्माण के पहले मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है। मिट्टी की जाँच प्रयोगशाला में ले जाकर करवाना चाहिये।जहां तालाब बनाना हो उस स्थान पर 3 x 3 फीट के क्षेत्र में कम से कम 3-5 फीट का गड्ढा बना कर मिट्टी निकाले उस, मिट्टी को पाने में गीला कर 3 इंच व्यास का गोला बनाएं एवं 3-4 फीट तक हवा में उछाले। यदि गोला टूट जाए तो मिट्टी तालाब बनाने के उपयुक्त नहीं हैं, यदि गोला नहीं टूटे तो तालाब के लिए उपयुक्त है। दूसरी विधि यह है की, मिट्टी का गोला (3 इंच व्यास) बनाकर उसे बेलनाकार घुमा कर 5-6 इंच तक लंबा करे यदि नहीं टूटे तो यह स्थान तालाब के लिए उपयुक्त है।

तालाब का आकार

आयताकार तालाब ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 2– 3 : 1 रखना ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। क्योंकि यदि तालाब की चौड़ाई अधिक होगी तो उसमें जाल चलाना कठिन होता है तथा श्रमिकों के प्रति खर्च भी बढ़ जाता है। उपलब्ध जमीन का 70 से 75 प्रतिशत भाग ही तालाब के निर्माण हेतु अर्थात जलक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है, शेष 25-30 % तालाब के बाँध में चला जाता है। अर्थात एक एकड़ के तालाब के निर्माण हेतु लगभग 35 से 1.40 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है।पूरब पश्चिम दिशा में तालाबों को बनवाने से में हवा के बहाव के कारण पानी में अधिक हलचल होती रहती हैं जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है।बहुत बड़े तालाब में जाल चलाना कठिन हो जाता है।तालाब या पोखर ऐसे स्थिर जल निकाय को कहते हैं जो झील से छोटा होता है तथा कम से कम 4-6 माह जल भरा रहता है। मछली पालन इकाई के अंदर विभिन्न प्रकार के तालाब घटकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नर्सरी तालाब, पालन तालाब, उत्पादन, प्रजनन / स्पिनिंग पूल शामिल होते हैं। मछली के बढ़ते उम्र एक साथ उसको अलग अलग तालाब में रखा जाता हैं, ताकि उसे पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन एवं जगह मिल सके एवं वृद्धि अच्छी हो। तालाब के विभिन्न प्रकार निम्न है –

तालाब की औसत गहराई

तालाब की औसत गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। जहां पानी का साधन हो वहां तालाब की गहराई से 50-2.00 मी रखना चाहिए। यदि तालाब वर्षा पर आधारित ही वहां तालाब की गहराई 8-10 फीट तक रख सकते है।तालाब को पानी से पूरा न भरकर ऊपर कुछ क्षेत्र छोड़ना चाहिए,इसे फ्रीबोर्ड कहते हैं। सामान्यतः 25-1.50 मी० का जलस्तर उपयुक्त रहता है।कम गहरे तालाबों का ग्रीष्म ऋतु में सूखने का भय रहता है, तथा उचित गहरा होने पर प्रबंधन कठिन हो जाता है।अधिक गहरे तालाबों की तलहटी पर कार्बनिक - अकार्बनिक पदार्थों के एकत्रीकरण से विषैली गैस बनने का डर रहता है।

तालाब की संरचना

यदि आपके पास जमीन पर्याप्त मात्रा मे है तो तालाब के जलक्षेत्र को नापने के बाद चारों तरफ 2' से 3' फीट जमीन वर्म के रूप में छोडकर बाँध बनाया जाय जिससे बाँध की मिटटी को क्षरण होकर तालाब में जाने से रोका जा सके।तालाब की खड़ी खुदाई नहीं करनी चाहिए, तथा तालाब का किनारा ढलवां होना चाहिए। तालाब का ढालना 1:1.5 या 1:2 (ऊंचाई : आधार) रखा जाना चाहिये।तालाब का क्षेत्रफल पाली जाने वाली मत्स्य प्रजाति के साइज तथा संख्या पर निर्भर करता है।

तालाब के तल की बनावट

तालाब के तल को समतल होने के साथ साथ द्रढ़ भी होना चाहिए तथा जल के प्रवेश वाले स्थान से निकासी वाले स्थान की तरफ 1 से 2 प्रतिशत की ढलान का होना आवश्यक है। तालाब में ढलान होने के कारण जल निकासी का द्वार खोल देने पर पानी गुरुत्व के कारण बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मत्स्य निकासी के समय तालाब को आसानी से खाली किया जा सकता है। तालाब को हर फसल के बाद पूर्ण रूप से सुखाना चाहिए। यदि हर वर्ष संभव न हो तो 2 वर्ष में एक बार अवश्य सुखना चाहिए। तालाब का तल सुख जाने तक तालाब को सुखाना आवश्यक है, इससे हानिकारक जीव का विनाश हो जाता है। तालाब को खाली करके और उसे धुप में सुखाकर तालाब को सुखाया जाता है। यह तब तक किया जाता है जब तक की जमीन की मिटटी सुख न जाये और उसमे दरारें न पड़ जाये। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 7 दिन का समय लगता है लेकिन यह भी मौसम की स्थिति और मिटटी की विशेषताओं पर निर्भर करता है।

तालाब का बांध निर्माण

तालाब का बांध सामान्यतः चिकनी दोमट मिटटी का ही बनाना चाहिए एवं मजबूत होना चाहिये, क्योंकि कि वह पानी के दबाव को सेहता है तथा पानी को रिसने से रोकता है। बाँध निर्माण हेतु निम्नलिखित बातें आवश्यक है –जिस जगह तालाब बनाना हो उस भूमि में अवांछित चीजे जैसे पेड़ों, झाड़ियों, पत्थरों और चट्टानों को हटाकर भूमि तैयार की जानी चाहिए। तालाब बनाने के पूर्व भूमि की उस जगह जहां मिटटी की खुदाई होती है, वर्म का स्थान एवं बाँध का निर्माण स्थल को चुन से चिन्हित कर लेना आवश्यक है।चिन्हित स्थल से घास व पौधों को हटा कर ट्रैक्टर या हल से जुताई करने के बाद ही वहां पर मिटटी डालने का काम किया जाए, इससे बांध मजबूत बनेगा और पानी के रिसाव की संभावना नहीं रहेगी।जिस तरफ पानी का रिसाव हो उधर का बाँध ज्यादा चौड़ा एवं मजबूत बनाना चाहिए।शिखर की चौड़ाई के अनुरूप बाँध के दोनों ओर ढलान रखना आवश्यक है यदि बाँध की उंचाई 3 -4 फीट हो, तो शिखर की चौड़ाई भी कम से कम 4-5 फीट रखनी चाहिये।

केला की उन्नत और जैविक खेती : कम खर्च में दोगुनी कमाई

कृषि डेस्क

भारत में केला की बागवानी प्रायः हर इलाके में होती है। यह बात और है कि केला की खेती आज भी लोग नहीं करते। घर के आसपास कुछ केले के पौधे के जरिये लोग केला खाने का ही आनंद उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से अब केला की खेती व्यावसायिक रूप ले रही है ,ऐसे में किसान तोड़ी सतर्कता के साथ खेला की बागवानी वैज्ञानिक तरीके से लगाए तो उनकी कमाई खूब हो सकती है। बड़ी बात तो यही है कि कम खर्च में केला की बागवानी करके अच्छा मुनाफा मिल जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर किसान केले की खेती में रुचि लेने लगे हैं। भारत में पुराने समय से ही केले का बड़ा ही महत्व है. चाहे धार्मिक अनुष्ठान हों या पोषण की कमी को पूरा करना हो, केला अपने आप में पावर बूस्टर फल का काम करता है। केला एक प्रमुख नकदी फसल भी है, जो कम खर्च में अधिक मुनाफा दे जाती है। इसकी एक बार रोपाई करने के बाद अगले 5 साल तक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। भारत में भी साल भर केले की खपत बनी रहती है। यही कारण है कि ज्यादातर किसान अब केले की खेती में रुचि ले रहे हैं।

लागत और आमदनी

केले की खेती को आम भाषा में 'वन टाइम इन्वेस्टमेंट' बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। इसके बागों को लगाने में 50,000 रुपये की शुरुआती लागत आती है, जिसमें नर्सरी की तैयारी, बीज, खाद-उर्वरक, पौधों की रोपाई और सिंचाई आदि शामिल है। अगर जैविक विधि से केले की बागवानी करते हैं तो भविष्य में केले का सिर्फ एक पौधा 60-70 किलो तक का फल उत्पादन दे सकता है। इसकी खेती के लिये ज्यादा खर्च नहीं आता, लेकिन कम लागत में अच्छी आमदनी लेने के लिये केले की जैविक खेती करने की सलाह दी जाती है। केले की पुरानी फसल से निकला अपशिष्ट-कचरा भी खेत के लिये जैविक खाद के तौर पर पोषण देने का काम करता है। केला को कम जोखिम वाली फसल कहते हैं, लेकिन खेती में मौसम के रिस्क को कम करने के लिये फसल का बीमा करवाना फायदेमंद रहता है।

उन्नत किस्मों से करें खेती

भारत में जलवायु और मिट्टी के हिसाब से केले की 500 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। केले की बागवानी से मोटी कमाई हासिल करने के लिये इसकी उन्नत, रोग प्रतिरोधी और अच्छी पैदावार देने वाली किस्में ही लगानी चाहिये।

नेंद्रन केला

केला की नेंद्रन किस्म को कम खर्च में ज्यादा उत्पादन और मुनाफा देने वाली फसल भी कहते हैं. यही कारण है कि दक्षिण भारत के ज्यादातर किसानों की पहली पसंद नेंद्रन केला ही है। इस केले की खेती के बाद प्रसंस्करण करके चिप्स और पाउडर बनाया जाता है, जिससे किसानों को अच्छा पैसा मिल जाता है।

मोन्थन केला

मोन्थन केला को बिहार से लेकर केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। आमतौर पर मोन्थन केला के फल का बीच वाला हिस्सा सख्त होता है, जिसके चलते इसे ज्यादातर सब्जी और दूसरे प्रसंस्करित उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हर सीजन में इस केले सिर्फ एक ही पौधे से 18-22 किग्रा का उत्पादन मिल जाता है। लेकिन कोंकण गोवा के इलाकों में इसकी सह-फसली खेती करके का काफी चलन है।

कारपुरावल्ली केला

यह केला की लंबी अवधि वाली किस्म है, जिससे 20-25 किग्रा प्रति पौधे के हिसाब से उत्पादन मिल जाता है। केले की ये किस्म कम लागत में अच्छी बढ़वार हासिल कर लेती है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों का भी इस पर कुछ खास असर नहीं होता। यही कारण है कि तमिलनाडु के ज्यादातर बागों में कारपुरावल्ली केला की फसल लगाते हैं। इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में भी किया जाता है।

क्या नेपाल में फिर लौटेगी राजशाही?

इंटरनेशनल डेस्क

नेपाल में एक बार फिर से लोकतंत्र के खिलाफ बयार बाह रही है और राजशाही के समर्थन में नारे लग रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेपाल की जनता की भावना बदल गई ? वाकई में लोग वहां लोकतंत्र से ऊब से गए हैं और क्या वाकई में नेपाली जनता राजशाही चाहती है ? कुछ और भी सवाल हैं। नेपाल कभी हिन्दू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। वहां लम्बे समय तक राजशाही थी। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी के सरोकार थे। सरोकार तो आज भी है लेकिन दोनों देशों के बीच अब बहुत कुछ वैसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज नेपाल कई मसलों पर भारत के खिलाफ जाता है और भारत के दुश्मनों के साथ बैठक भी करता है। कह सकते हैं कि जब तक नेपाल में राजशाही थी तब तक तब तक दोनों देशों के बीच मधुर सम्बन्ध थे। लगता था दोनों देश की सोंच और समझ एक ही है ,संस्कृति भी एक है और पूजा पाठ के रिवाज भी एक ही है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वहां अब एक संवैधानिक सेक्युलर सरकार है।

नेपाल ने 2008 में अपनी 239 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया, दो साल पहले बड़े पैमाने पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों ने ज्ञानेंद्र को पूर्ण शासन से हटने के लिए मजबूर किया था। देश एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, लेकिन तब से, कई नेपाली राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संघर्षों से निराश हो गए हैं। राजशाही के उन्मूलन के बाद से, नेपाल ने 13 अलग-अलग सरकारें देखी हैं, जिससे कई लोगों का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था विफल हो गई है। भ्रष्टाचार, आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक स्थिरता की कमी ने कुछ नागरिकों को राजशाही पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। ये सब नेपाकि के भीतर की आंत्रिक कहानी और जनता की सोंच। लेकिन बीते रविवार को काठमांडू की सड़कों पर "हमारे प्यारे राजा अमर रहें" और "राजा के लिए शाही महल खाली करो" के नारे गूंज रहे थे, जब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के हजारों समर्थक राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में बहाल करने की मांग करने के लिए एकत्र हुए थे।

अनुमानित 10,000 राजभक्तों ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया, जब ज्ञानेंद्र पश्चिमी नेपाल के दौरे से लौट रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराए और पूर्व राजा की बहाली की मांग करते हुए बैनर लिए हुए थे। प्रदर्शन ने हवाई अड्डे के संचालन को बाधित कर दिया, जिससे यात्रियों को टर्मिनल से आने-जाने के लिए पैदल चलना पड़ा, जबकि सैकड़ों दंगा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने से रोक दिया। विरोध की तीव्रता के बावजूद, किसी भी हिंसा की सूचना नहीं मिली।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "मैं राजशाही को खत्म करने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल था, मुझे उम्मीद थी कि इससे देश को मदद मिलेगी, लेकिन मैं गलत था। देश और भी डूब गया है, इसलिए मैंने अपना विचार बदल दिया है।" अब बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ज्ञानेंद्र सत्ता में वापस आ सकते हैं? बढ़ते समर्थन के बावजूद, ज्ञानेंद्र ने अपनी वापसी के लिए नए सिरे से की जा रही मांगों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में उनके सिंहासन पर फिर से काबिज होने की संभावना कम है। गणतंत्र संवैधानिक रूप से स्थापित है, और मुख्यधारा के राजनीतिक दल राजशाही को फिर से स्थापित करने का विरोध करते हैं। ज्ञानेंद्र, जो अपने भाई राजा बीरेंद्र और उनके परिवार के दुखद नरसंहार के बाद 2002 में पहली बार राजा बने थे, ने शुरू में एक संवैधानिक सम्राट के रूप में शासन किया। हालांकि, 2005 में, उन्होंने सरकार और संसद को भंग करके, राजनेताओं और पत्रकारों को जेल में डालकर, और आपातकालीन शासन लागू करके पूर्ण शक्ति पर कब्ज़ा कर लिया। उनके सत्तावादी शासन ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः राजशाही को समाप्त कर दिया गया।

आगे क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता लेकिन एक बात सच है कि आज भी नेपाल में राजभक्तों की कमी नहीं है। बड़ी संख्या में आज भी ऐसे लोग हैं जो पूर्व राज परिवार का शासन चाहते हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल में लोग सरकार से काफ़ी निराश हैं और इसी से राजतंत्र के समर्थकों को मौक़ा मिला है। नेपाल में कुछ भी होता है तो भारत पर सबकी नज़र रहती है। रविवार को काठमांडू में ज्ञानेंद्र के स्वागत में आई भीड़ में से एक शख़्स ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर खड़ा था। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखने के बाद से नेपाल में बहस शुरू हो गई है कि क्या इस आंदोलन का भारत से भी संबंध है?

के पी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से जुड़े एक बड़े नेता विष्णु रिजाल ने कहा है कि ''जिस योगी की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किया गया, उसी योगी ने ज्ञानेंद्र को कुंभ में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया जबकि इसी कुंभ में 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई. ऐसा तब है, जब ज्ञानेंद्र ख़ुद को हिन्दू हृदय सम्राट कहते हैं। गणतंत्र का विरोध करते हुए उन्होंने इसे विदेशियों की व्यवस्था कहा है। ऐसा कहकर उन्होंने जनता का अपमान तो किया ही है लेकिन फिर से राजा बनने के लिए विदेशियों की दलाली करने से कथित राष्ट्रवाद का मुखौटा भी अच्छी तरह से उतर गया है।''

योगी की तस्वीर का हवाला देकर विष्णु रिजाल कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र राजा बनने के लिए 'विदेशियों की दलाली कर रहे हैं'। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता रविंद्र मिश्र कहते हैं, ''सरकार हमारे आंदोलन से डर गई है। सरकार से लोगों का मोहभंग हो रहा है और लोग राजतंत्र के समर्थन में आ रहे हैं। हमारे आंदोलन को रोकने के लिए ही सरकार ने काठमांडू में दो महीने की निषेधाज्ञा लगा दी है। ख़ास करके नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि ये सरकार में होती हैं तो भारत के साथ होती हैं और सत्ता से बाहर रहने पर भारत को गालियाँ देती हैं। इन्हें लगता है कि भारत को गाली देना ही राष्ट्रवाद है। ''

आगे नेपाली जनता क्या कुछ करती है यह देखने की बात हो सकती है लेकिन यह भी साफ़ है कि नेपाल के हिन्दू राष्ट्र की चाहत भारत में भी बहुत से लोग रखते हैं। बीजेपी और संघ के कई नेता नेपाल को हिन्दू राष्ट्र पर फक्र भी करते रहे हैं और इन्ही नेताओं में सीएम योगी भी हैं। आगे नेपाल में क्या कुछ होगा और जनता की मांग कितनी प्रबल होगी यह तो वक्त ही बतायेगा लेकिन जिस तरह से नेपाल में राजशाही की मांग बढ़ रही है उसे देखते हुए किसी बड़े आंदोलन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

पाकिस्तान में अलग बलूचिस्तान देश की मांग, बीएलए ने किया ट्रेन को हाईजैक

इंटरनेशनल डेस्क

पाकिस्तान सेना ने कम से कम 155 बंधकों को बलूच लिबरेशन आर्मी से मुक्त करा लिया है। इनमें 58 पुरुष, 31 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं। इन यात्रियों को पास के माच शहर में स्थित अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 27 विद्रोही भी मारे गए हैं। बता दें कि बीते मंगलवार को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान की एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके उसे अगवा कर लिया था। बीएलए ने बयान जारी करके कहा कि ट्रेन में सवार 182 यात्रियों को बंधक बना लिया गया है, जबकि पाकिस्तान के 20 सैनिकों की हत्या कर दी है। बीएलए ने यह भी दावा किया है कि उसने एक ड्रोन भी मार गिराया है। पाकिस्तान की पूरी ट्रेन बलूच आर्मी के कब्जे में है और एक सुरंग में खड़ी है। बलूच विद्रोहियों ने जिस अंदाज में यह सब किया है उससे साफ़ है कि बलूच लोग किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वे आजादी चाहते हैं और अलग बलूचिस्तान की मांग करते हैं। पाकिस्तान के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

बंधक ट्रेन का आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाह लगी है। बड़ी खबर ये है कि जहाँ ट्रेन खड़ी है उसके आगे और पीछे के पटरियों को भी उड़ा दिया गया है। मंगलवार देर रात को ही बीएलए ने एक बयान जारी कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी जेलों में बंद बलूच कैदियों को नहीं छोड़ा गया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। बीएलए ने यह भी कह दिया है कि अगर सरकार कोई सेना की कार्रवाई करती है तो भी बंधकों को मार दिया जाएगा। बीएलए की प्रमुख मांग तो यही है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। बलूचिस्तान एक अलग देश की मांग कर रहा है। बता दें कि बलूचिस्तान से होकर चीन का सीपिक प्रोजेक्ट गुजरता है और बलूच आर्मी इस प्रोजेक्ट का विरोध करती है। यह भी बता दें कि पिछले चार साल में बीएलए के 76 हमले में 1156 पाकिस्तानी सेना भी मारे गए हैं। उधर रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि सच तो यही है कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वाह पूरी तरह से फिसल चुके हैं। पाकिस्तानी सेना यहाँ पिछले 75 सालों से दमन का चक्र चला रही है लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। सच तो यही है कि इन दोनों क्षेत्रों में बागियों की अपनी समानान्तर सरकार चलती है ,और पाक सेना यहाँ एक रबर स्टैम्प है। लेकिन अब पीओके में भी जान आंदोलन शुरू हो गया है और यह सब पाकिस्तान सेना के सामने बड़ी चुनौती है।

बता दें कि ट्रेन हाई जैक यह हमला मंगलवार को दोपहर करीब एक बजे क्वेटा से पेशावर के रूट पर बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में हुआ। छह घंटे बाद शाम साढ़े सात बजे तक जाफर एक्सप्रेस पूरी तरह से बीएलए के लड़ाकों के नियंत्रण में थी। पिछले साल 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात बीएलए ने इस ट्रेन के रूट में एक पुल को उड़ा दिया था। इसके चलते ट्रेन की सेवा रोक दी गई थी। 11 अक्टूबर 2024 को ट्रेन सेवा फिर से शुरू हुई थी। बहरहाल, बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के माशकाफ में गुडालार और पीरू कुनरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया। यह पहाड़ी इलाका है, जहां 17 सुरंगें हैं, इसके चलते ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर बीएलए ने ट्रेन पर हमला किया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने माशकाफ में टनल नंबर आठ में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इसके बाद बीएलए ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में ट्रेन का ड्राइवर भी घायल हुआ।

इस ट्रेन में सुरक्षा बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग सफर कर रहे थे। सभी पंजाब जा रहे थे। इन्होंने बीएलए के हमले का जवाब दिया। लेकिन बीएलए ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। पहले 11 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की खबर आई थी लेकिन बाद में बीएलए ने कहा कि उसने 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। घटना की जानकारी मिलने पर पाकिस्तान सेना ने बीएलए पर जमीनी फायरिंग की और हवा से बम भी बरसाए। लेकिन बलूच आर्मी के लड़ाकों ने किसी तरह सेना के जमीनी ऑपरेशन को रोक दिया। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने तुरंत इस इलाके की ओर एक ट्रेन रवाना की, जिसमें मदद के लिए सैनिकों को भी भेजा गया है। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, 'हम ऐसे जानवरों से कोई समझौता नहीं करेंगे, जिन्होंने बेकसूर यात्रियों पर गोलीबारी की'। दूसरी ओर एक बयान में बीएलए ने कहा, 'हमारे लड़ाकों ने माशकाफ, धादर और बोलान में इस ऑपरेशन को प्लान किया। हमने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस रुकना पड़ा। इसके बाद हमारे लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया'। बीएलए ने कहा, 'बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के कर्मचारी शामिल हैं, जो पंजाब जा रहे थे। हमने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को छोड़ दिया है, सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मियों को बंधक बनाया गया है'।

चैम्पियंस ट्रॉफी में जीत के बाद नोटों की बरसात

खेल डेस्क

भारत ने टूर्नामेंट में एक भी मैच गंवाये बिना 2002 और 2013 के बाद तीसरी बार खिताब जीता। कोई दूसरी टीम तीन बार यह ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। विजेता भारत पर पैसों की बारिश हुई है। भारतीय टीम को 2.4 मिलियन अमेरिका डॉलर यानी करीब 19.5 करोड़ रुपये मिले। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनामी राशि में पिछली बार की तुलना में 53 प्रतिशत का इजाफा किया था।

विजेता के अलावा उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम को 1.12 मिलियन डॉलर यानी करीब 9.72 करोड़ रुपये मिले, जबकि सेमीफाइनल में बाहर होने वाली दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को 56000 डॉलर यानी 4.86 करोड़ रुपये मिले। इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि बढ़कर 6.9 मिलियन डॉलर (करीब 60 करोड़ रुपये) हुई थी। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने एक बयान में कहा था, पर्याप्त पुरस्कार राशि खेल में निवेश करने और हमारे आयोजनों की वैश्विक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आईसीसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

किसी भी टीम को ग्रुप चरण में जीत हासिल करने पर 34,000 डॉलर (30 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि मिली। पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 350000 डॉलर (करीब तीन करोड़ रुपये), जबकि सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को 140000 डॉलर (करीब 1.2 करोड़ रुपये) मिले। इसके अतिरिक्त सभी आठ टीमों को इस आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 125000 डॉलर (करीब 1.08) करोड़ रुपये की राशि दी गई।

स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएंगे आईपीएल 2025

खेल डेस्क

खेल प्रेमियों को इस बात से सदमा लग सकता है कि उनके प्रिय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2025 में शामिल नहीं हो पाएंगे।ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंतिम मैच के दौरान बुमराह को गंभीर चोट लगी थी, जिसके चलते उन्हें खेल से कुछ समय का ब्रेक लेना पड़ा। हालांकि हाल ही में जसप्रीत बुमराह को प्रैक्टिस करते हुए देखा गया था, जिससे फैंस के बीच उनकी वापसी को लेकर उम्मीदें जागने लगी थीं। लेकिन अब उनकी फिटनेस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने मुंबई इंडियंस और उनके प्रशंसकों को झटका दिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जसप्रीत बुमराह को मैदान पर वापस लौटने के लिए अभी और समय का इंतजार करना पड़ सकता है। इसका सीधा असर IPL 2025 पर पड़ सकता है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि बुमराह शुरुआती कुछ हफ्तों में मुंबई इंडियंस के लिए मैदान पर नहीं उतर पाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुमराह इस समय अपनी फिटनेस को बेहतर करने के लिए नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, बुमराह की रिकवरी की रफ्तार अच्छी है और उन्होंने हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है।लेकिन मेडिकल टीम की मानें तो बुमराह को पूरी तरह फिट

होने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है। यही कारण है कि उनकी IPL 2025 के शुरुआती दो हफ्तों में मैदान पर वापसी की संभावना काफी कम है।

सूत्रों के मुताबिक, बीसीसीआई और मुंबई इंडियंस की मेडिकल टीम बुमराह की फिटनेस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि उनकी फिटनेस टीम इंडिया के लिए भी काफी मायने रखती है, खासकर इस साल के अंत में होने वाले बड़े टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखते हुए।ऐसे में कोई भी जोखिम उठाना सही नहीं होगा। यही कारण है कि मुंबई इंडियंस और बीसीसीआई दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुमराह अपनी पूरी फिटनेस हासिल करने के बाद ही मैदान पर लौटें, ताकि वह लंबे समय तक क्रिकेट खेल सकें।

बिहार की सत्ता के खेल को उजागर करती हुमा की 'महारानी' का जलवा

फिल्म डेस्क

बिहार की पृष्ठभूमि पर बखूबी सत्ता के खेल को दिखाने वाली वेब सीरीज 'महारानी' के चौथे सीजन का टीजर आउट हो चुका है। दमदार डायलॉग्स से भरे टीजर के जरिए 'रानी भारती' की दमदार वापसी देखने को मिली।टीजर वीडियो में रानी भारती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री हुमा कुरैशी एक कुर्सी पर बैठे हुए दमदार डायलॉग बोलती नजर आती हैं। टीजर वीडियो की शुरुआत में हुमा कहती हैं कि उन्हें हत्यारा, अनपढ़ और भावी प्रधानमंत्री कहा गया है। हालांकि, उनके लिए उनका परिवार राजनीति से ज्यादा मायने रखता है और बिहार ही उनका परिवार है। वह कहती हैं, "किसी ने हमको गंवार कहा, किसी ने हत्यारन, तो किसी ने भावी प्रधानमंत्री। हमको सत्ता से नहीं, परिवार से मोह है। काहे कि बिहार ही हमरा असली परिवार है और अगर कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए तो हम सत्ता हिला देंगे।" महारानी 4 के साथ रानी भारती पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ वापसी के लिए तैयार हैं, जिसमें नई चुनौतियां और संघर्ष भी देखने को मिलेगी।

हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक सीरीज के रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है। 'महारानी' का पहला सीजन साल 2021 में सोनी लिव पर आया था। इस सीरीज में अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने रानी भारती का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। हुमा के किरदार पर नजर डालें तो वह एक साधारण और अनपढ़ गृहिणी के किरदार में हैं, जिसे अचानक से राजनीति में कदम रखना पड़ता है। वह अपने पति भीमा के चोटिल होने के बाद बिहार की मुख्यमंत्री बनती हैं। सीरीज में हुमा के पति का किरदार अभिनेता सोहम शाह ने निभाया है। सीरीज का दूसरा सीजन जुलाई 2022 में आया, वहीं तीसरा सीजन 2024 में आया था। महारानी 4' की कहानी को उमाशंकर सिंह ने सुभाष कपूर और नंदन सिंह के साथ मिलकर लिखा है। निर्माण सुभाष कपूर ने किया है और निर्देशक सौरभ भावे हैं। सीरीज में हुमा कुरैशी के साथ अमित सियाल, विनीत कुमार, कनी कुसरुति, अनुजा साठे, सुशील पांडे, दिव्येंदु भट्टाचार्य, सोहम शाह और प्रमोद पाठक भी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड को टॉक्सिक क्यों कहा?

फिल्म डेस्क

क्या पूरा बॉलीवुड टॉक्सिक है ? बॉलीवुड के वातावरण में जहर ही जहर है ?और क्या बॉलीवुड को अब क्रिएटिव माहौल से चिढ होने लगी है और वह केवल पैसे कमाने के पीछे पागल है ? कुछ इसी तरह की बातें आजकल बॉलीवुड में खूब की जा रही है। अभी हाल में ही मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने एक साक्षात्कार के दौरान जो बातें कही है उससे साफ़ लगता है कि बॉलीवुड का पूरा माहौल ही बदल गया है और जहरीला होता जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक़ अब अनुराग कश्यप बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। यानी वे अब मुंबई से दूर दक्षिण चले गए हैं। अब वे वही रहेंगे और फिर अपने मन मुताबिक वही से काम करेंगे। उन्होंने द हिंदू के साथ इंटरव्यू में बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ अपनी निराशा जताई है। उन्होंने कहा, 'मैं फिल्म के लोगों से दूर रहना चाहता हूं। यह इंडस्ट्री बहुत टॉक्सिक हो गई है। सब अवास्तविक लक्ष्यों के पीछे पड़े है। सबको 500 या 800 करोड़ रुपए कमाने हैं। जो क्रिएटिव माहौल है वह खत्म हो गया है। अनुराग कश्यप ने इससे पहले बताया था कि वह हिंदी इंडस्ट्री से निराश और परेशान हो गए हैं और भारत से साउथ में जाने की प्लानिंग में हैं। उन्होंने कहा, 'मैं साउथ के फिल्ममेकर्स से जलन करता हूं क्योंकि अब, मेरे लिए बाहर जाकर प्रयोग करना मुश्किल है। क्योंकि अब, यह एक लागत पर आता है, जो मेरे निर्माताओं को लाभ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वे कहते हैं, 'मेरे मार्जिन कहां हैं? मैं पैसे खो रहा हूं.' मैं कहता हूं, 'आप यह फिल्म नहीं बनाना चाहते तो यह फिल्म मत बनाइए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि शुरुआत से ही, फिल्म शुरू होने से पहले, यह इस बारे में हो जाता है कि 'हम इसे कैसे बेचेंगे?' इसलिए फिल्म निर्माण का आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूं। सचमुच, अगले साल, मैं मुंबई से बाहर जा रहा हूं। फिल्म निर्माता कश्यप फिलहाल मलयालम फिल्म फुटेज का प्रमोशन कर रहे हैं, जिसका निर्देशन सैजू श्रीधरन ने किया है। इस फिल्म में मंजू वारियर के साथ विशाक नायर और गायत्री अशोक लीड रोल में हैं। यह फिल्म पिछले साल अगस्त में रिलीज हुई थी, लेकिन इसका हिंदी वर्जन अब रिलीज होने वाला है। इसके बाद अनुराग कश्यप फिल्म डकैत में एक निडर पुलिस वाले का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे।

पत्रकारिता को नए सिरे से परिभाषित करते हुए न्यू देहली पोस्ट की शानदार प्रस्तुति अब आपके सामने है। इसमें होगी खोजी और जानबूझ कर दबाई गई ख़बरों के उद्भेदन की शानदार प्रस्तुति - न्यू दिल्ली पोस्ट प्रिंट और डिजिटल के सभी मंचो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है :-

न्यू देहली पोस्ट
(साप्ताहिक हिंदी)

हमारे ये सभी डिजिटल मंच सभी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। यहाँ जाकर आप ताजातरीन ख़बरों और विश्लेषण को देख समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं।

Website: https://newdelhipost.co.in/
: @NewDelhiPost
: https://www.facebook.com/NewDelhiPosts
: @NewDelhiPost
:newdelhipost_official

न्यू देहली पोस्ट
B-614, 6th Floor Tower B
Noida One Building
Noida Sector 62, Gautam Budh Nagar (UP)
Pin Code -201309

संपर्क करे - Email - postnewdelhi@gmail.com